

राजस्थान सुजस

मुख्यमंत्री
वृक्षारोपण
महा अभियान



**वृक्षो रक्षति रक्षितः,
तस्मात् रक्षतु वृक्षकः**

“आप पेड़ों की रक्षा करें
और पेड़ आपकी रक्षा करेंगे।”



आइए ! हम सभी मिलकर पर्यावरण को शुद्ध करें, उसकी सुरक्षा करें और इस प्रकृति को सहेजकर रखने का संकल्प लें।

प्रकृति हमें सब कुछ देती है, तो हमें भी उसे कुछ लौटाना सीखना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण के प्रति सजग रहें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, ताकि वे भी इसके प्रति जागरूक बनें। हमें यह सोचना होगा कि प्रकृति का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? हमें स्वयं इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए और अपने कार्यों से दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को लेकर जो अभियान शुरू किया है, वह अब पूरे देश का जन-आंदोलन बन गया है।

‘एक पेड़ - माँ के नाम’ अभियान भी एक महान पहल है। इस अभियान से जब कोई व्यक्ति जुड़ता है और कहता है कि उसने अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया है, तो यह बात हर किसी के दिल को छूती है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, जो अपनी माँ से प्रेम न करता हो। हमारी माँ है, धरती माँ है, गंगा माँ है, गौ माँ है। ‘एक पेड़ - माँ के नाम’ अभियान से प्रेरणा लेकर, हमारी सरकार ने राजस्थान को हरा-भरा बनाने का संकल्प किया है। हमारा लक्ष्य है कि पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण किया जाए। इस अभियान के तहत पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। इस साल भी हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने इस लक्ष्य को पार कर लिया है।

हम सभी के लिए प्रकृति की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि हमें प्रकृति को सहेजकर रखना है। इस धरती पर जितने भी जीव-जंतु हैं, वे सभी किसी-न-किसी पर निर्भर हैं। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। सरकार इस दिशा में पूरी निष्ठा से काम कर रही है। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पिछले डेढ़ वर्ष में हमने इस दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। राम-जल सेतु लिंक परियोजना हो या यमुना जल समझौता, हमने इन सभी पर गंभीरता से कार्य किया है। माही डैम से उदयपुर और बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों को पानी उपलब्ध करवाया गया है। देवास स्कीम भी संचालित की जा रही है, जिससे चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद को पानी मिलेगा।

अर्थात्, पूरे राजस्थान में हम जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रकृति को लेकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। आइए, हम सभी मिलकर पर्यावरण को शुद्ध करें, उसकी सुरक्षा करें और इस प्रकृति को सहेजकर रखने का संकल्प लें। ■

– मुख्यमंत्री



प्रधान संपादक
संदेश नायक

संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
रेनबो ऑफसेट प्रिंटेर्स
लागत मूल्य 00.00 रुपये

संपर्क

संपादक

राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80581 15790

e-mail

editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in

Website

www.dipr.rajasthan.gov.in



79वां
स्वतंत्रता दिवस



आज़ादी का उत्सव

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 34 अंक 08

इस अंक में

अगस्त, 2025



पल्लवित वृक्ष,
हरित संसार

05



मेहमान परिंदों का
आसरा : मेनार वेटलैंड
कॉम्प्लेक्स

26



वन्यजीव संरक्षण
एवं इको टूरिज्म

30

शब्द भावना	02
संपादकीय	04
आज़ादी का उत्सव	08
ई-वेस्ट : सही प्रबंधन ही उपचार	12
राजस्थानी चित्रशैलियों में वनस्पति	14
ग्राम पंचायतों में खुले बर्तन बैंक	17
संरक्षित पहाड़, समृद्ध शहर	18
राजस्थान के देशज पौधों में छिपा ...	20
मैं सरिस्का हूँ ...	22
ऊँची उड़ान का राजा	25
मछली वन की रानी है ...	28
खेजड़ी : रूत आया पांघरसी	37
हरित धरा संग डिजिटल धारा	38
युवा संसद - पक्ष विपक्ष एक हुए	42
कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट	43
जल-जंगल-जीवन की जननी - अरावली	44
खनन में पर्यावरण का ध्यान	46
कान्हा के वचन, गीता के आदर्श ...	48
संस्कृति से प्रकृति तक	52
सामयिकी	55
सुजस प्रश्नोत्तरी	62



ओरण हमारी धरोहर

40



भाई का वचन,
बहन की आस

50



हवा महल का 'पुरखा'

63



प्रकृति संग सह-अस्तित्व का संकल्प



प्रकृति हमारे अस्तित्व की आधारशिला है। यही हमें शुद्ध वायु, निर्मल जल, अन्न, औषधि और जीवन जीने के अनगिनत साधन प्रदान करती है, लेकिन आज जब विकास की दौड़ ने पर्यावरण पर दबाव बढ़ा दिया है, तब सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम प्रकृति को संजोएं, उसका संरक्षण करें और उसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी रखें। यह मात्र कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की शर्त है।

राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कई दूरदर्शी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए 'एक पेड़ - मां के नाम' अभियान जैसी संवेदनशील पहल से प्रेरणा लेकर शुरू किया गया 'हरयालो राजस्थान मिशन' आज जन-आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस वर्ष अगस्त मध्य तक ही 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश की धरा को धूसर से हरित बनाने की यह साधना आसान नहीं थी। सरकार ने पौधों की जियो-टैगिंग से लेकर उनकी देखभाल तक की व्यवस्था सुनिश्चित की, जल संरक्षण योजनाओं को मजबूती दी और समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़ा। परिणाम यह है कि जहां कभी दूर-दूर तक बंजर धरती दिखती थी, वहां अब जीवनदायिनी जीवंत हरियाली नजर आ रही है।

आज जब राजस्थान विकास के साथ समृद्ध व संरक्षित पर्यावरण की नई पहचान गढ़ रहा है, तब हम सभी का यह कर्तव्य है कि इस पहल का हिस्सा बनें। मन में धारण करें कि हर पौधा हमारी जिम्मेदारी है, हर जल स्रोत हमारी धरोहर है और हर पर्यावरणीय परिदृश्य हमारी चेतना का प्रतीक है। सरकार ने दिशा दिखाई है, अब हम सभी को इसे संकल्प और सहयोग से आगे बढ़ाना है। यही आगामी पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार और हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

राजस्थान की भूमि केवल शौर्य और संस्कृति के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहां का प्राकृतिक वैभव भी उतना ही अनूठा है। थार के रेगिस्तान से लेकर अरावली की हरियाली तक और रणथंभौर, सरिस्का, कुम्भलगढ़ जैसे राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर विशिष्ट जैव विविधता वाले अभयारण्यों तक-हर कोना हमें यह याद दिलाता है कि जीवन और प्रकृति का रिश्ता अविभाज्य है।

पर्यावरण संरक्षण के विविध आयामों तथा राज्य के कतिपय राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित जानकारी को समेटे अगस्त माह का यह अंक हम आप सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

(संदेश नायक)
प्रधान सम्पादक

पल्लवित वृक्ष, हरित संसार प्रकृति की छांव, सुख-शांति का आधार



दशकूप समो वापी, दशवापी समो हृदः।
दशहृद समः पुत्रो, दशपुत्र समो द्रुमः॥

— मत्स्य पुराण

इस श्लोक में प्रकृति, विशेष रूप से वृक्षों के महत्व को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया है। इसमें बताया गया है कि दस कुओं (दशकूप) के बराबर एक बावड़ी (वापी) है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब (हृद) है, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष (द्रुम) है। यह तुलना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि वृक्षों का सामाजिक, पारिवारिक, आध्यत्मिक और पर्यावरणीय महत्व कितना गहरा और बहुआयामी है। एक वृक्ष न केवल जीवनदायिनी प्राणवायु (ऑक्सीजन) देता है, बल्कि जल-संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पेड़ को पुत्र से बढ़कर माना जाना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति और जीवन के बीच हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है। यही भाव आज के पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में और अधिक प्रासंगिक हो चला है।



राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के क्रम में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर 3 हजार 500 से अधिक वन मित्र बनाए गए हैं। वहीं, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और इसे हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये की हरित अरावली विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है। हरित राजस्थान बनाने के प्रयासों के साथ पहली बार प्रदेश में 'ग्रीन बजट' भी पेश किया गया है। हमने वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के माध्यम से जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक पहल की है। इसके अन्तर्गत 42 हजार से ज्यादा जल स्रोतों की सफाई हुई। वहीं, 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' चलाकर 45 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

— मुख्यमंत्री



10 करोड़ पौधों का हरित वितान

मिशन “हरयालो राजस्थान”

– पवन कुमार उपाध्याय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार ने मिशन “हरयालो राजस्थान” प्रारंभ करने की बजट घोषणा की, जिसके तहत 5 वर्षों में प्रति वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया।

इस मिशन का उद्देश्य राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करना है। इसके साथ ही प्रदेश में कृषि-वानिकी को विकसित करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना तथा भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता की दिशा में अग्रसर करने में राजस्थान प्रदेश की अग्रिम भूमिका को सुनिश्चित करना है। यह पहल राजस्थान को सतत विकास की ओर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान’ के तहत वन विभाग द्वारा 80 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर 2.50 करोड़ पौधे तथा विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और आमजन आदि द्वारा 4.72 करोड़ पौधे रोपित किए गए। इस प्रकार कुल 7.22 करोड़ पौधों का रोपण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की गई है।

चूंरहा सफर.....

राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरणीय सन्तुलन, हरित आवरण में वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु ‘हरयालो राजस्थान’ मिशन के तहत वृक्षारोपण को जनआंदोलन का रूप दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट वर्ष 2025-26 में यह घोषणा की गयी “माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ किये गये ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से प्रेरणा लेकर पिछले वर्ष प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है।”

इसी क्रम में वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यापक तैयारियों की गईं। विभागीय 570 नर्सरियों में नाबाई, आर.एफ.बी.पी. रिवॉल्विंग फण्ड, फार्म फोरेस्ट्री, आर.एफ.बी.डी.पी. योजना के अंतर्गत 5.81 करोड़ छायादार, फूलदार, फलदार इत्यादि पौधों को तैयार किया गया, जिनका वितरण कार्य 04 जून, 2025 से प्रारम्भ हुआ।

इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ पौध तैयार कर उन्हें वन भूमि पर मानसून के



दौरान रोपित किया गया। साथ ही थांवला, ट्रेन्चेज एवं खाई फेन्सिंग जैसे उपायों के माध्यम से बीजारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। विभिन्न हितधारक विभागों को 23 अप्रैल, 2025 को पौधारोपण एवं वितरण हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए थे। यह वृक्षारोपण अभियान जन प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों, एन.सी.सी., स्काउट, पुलिस, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, मीडिया आदि के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की

570 नर्सरियों की सूची विभागीय FMDSS पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई। मिशन की निगरानी एवं पारदर्शिता के लिए 'हरयालो ऐप' का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर समस्त हितधारकों को पौधों की जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया। संभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर अपलोडिंग की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है।

आमजन की अधिकतम भागीदारी हेतु जिला कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसरों में अस्थायी स्टॉल्स लगाए गए। इसके साथ ही अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से पौध वितरण किया गया। राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी विभागों को अपने कार्यालय परिसरों में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण करने हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा निर्देशित किया गया। 19 अगस्त, 2025 तक वन विभाग की विभिन्न नर्सरियों से 4.24 करोड़ पौधे विभिन्न हितधारकों को वितरित किए गए हैं, जो 5.81 करोड़ वितरण लक्ष्य के विरुद्ध 72.98 प्रतिशत की उल्लेखनीय उपलब्धि है।

पौधारोपण के क्षेत्र में प्रदेश में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। 10 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य के विरुद्ध 10.07 करोड़ पौधारोपण कर मिशन 'हरयालो राजस्थान' के अंतर्गत यह लक्ष्य अगस्त मध्य तक पार कर लिया गया है। हरयालो राजस्थान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक बन चुका है। ■

10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य अर्जित



'हरयालो राजस्थान' अभियान के तहत प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में मुख्यमंत्री से वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात कर बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मिशन हरयालो राजस्थान के पोस्टर का विमोचन किया। वन मंत्री ने मुख्यमंत्री को पौधा भी भेंट किया। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरणा लेकर, हमारी सरकार ने राजस्थान को हरा-भरा बनाने का संकल्प किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने पिछले साल हरियाली तीज के पर्व पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत 'हरयालो राजस्थान' का शुभारंभ किया था। हमारा लक्ष्य है कि 50 करोड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण किया जाए। अभियान अंतर्गत पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेशवासियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पौधारोपण सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हरित भविष्य देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरयालो राजस्थान अभियान के तहत आमजन से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की अपील की। ■

79वां
स्वतंत्रता दिवस



आज़ादी का उत्सव



राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने राजभवन में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झण्डारोहण कर प्रदेश एवं राष्ट्र की समृद्धि व सम्पन्नता हेतु मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।



“स्वतंत्रता दिवस हमें अपने कर्तव्यों और राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह दिन अतीत के संघर्ष का स्मरण ही नहीं कराता, बल्कि एकता, प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। हम सब मिलकर तिरंगे की शान को सदैव ऊंचा रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे।”

- मुख्यमंत्री

आज़ादी के रंगों से सराबोर सांस्कृतिक संध्या

स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के सम्राट अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भाग लिया, जहां कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। उन्होंने राजस्थान पुलिस की शस्त्र प्रदर्शनी व विभिन्न संस्थाओं के स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा हस्तशिल्पियों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोधपुर विकास प्राधिकरण की सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना और ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना की आवेदन पुस्तिका का विमोचन किया तथा पाल रोड स्थित नहर चौराहे पर फ्लाइंगओवर का शिलान्यास भी किया।





शौर्य और बलिदान को नमन

श्री शर्मा ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया और वीरगति को प्राप्त सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर उच्च अधिकारी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

विकसित राजस्थान का संकल्प

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर सर्किट हाउस पर ध्वजारोहण किया और बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर जवानों, पुलिसकर्मियों और समाजसेवी संस्थाओं के योगदान की सराहना की तथा 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' में 'जय अनुसंधान' जोड़ने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश जल आत्मनिर्भरता के लिए 'रामजल सेतु लिंक परियोजना', 'यमुना जल समझौता'

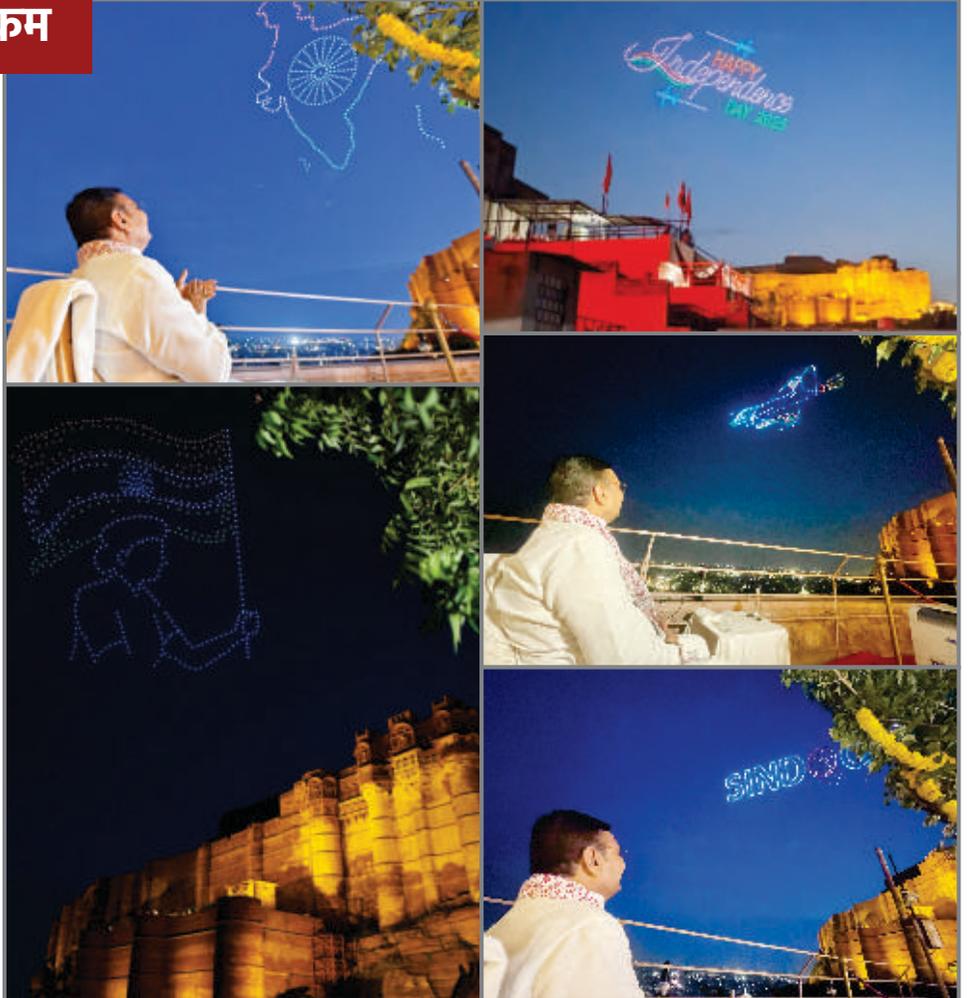
व 'मिशन हरयालो राजस्थान' के तहत 50 करोड़ पौधारोपण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता हेतु स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 से 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन और अगले 5 साल में 53 हजार किमी सड़क नेटवर्क का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। उन्होंने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक सफलता का उल्लेख किया और गरीबी मुक्त गांव, आयुष्मान, लखपति दीदी, मा वाउचर व लाडो प्रोत्साहन जैसी योजनाओं से वंचित वर्ग को राहत देने की बात कही। युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार

सृजन व 3 लाख कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, 3 महिला बटालियन और 65 एंटी रोमियो स्कवॉड शुरू किए गए हैं, साथ ही साइबर अपराध व गैंगस्टर्स से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। समारोह में हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, परेड, हथियार प्रदर्शन, घुड़सवारी, कैमल टैटू शो, बैंड व लोकनृत्य प्रस्तुतियां हुईं और चयनित अधिकारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय व राज्य के मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया।

जोधपुर में 'एट होम' कार्यक्रम

ड्रोन शो में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा

स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां उन्होंने 14 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 5 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर आधारित भव्य ड्रोन शो का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 550 ड्रोन ने आसमान में भारतीय सेना की शौर्य गाथा का मनोहारी प्रदर्शन किया। इस अद्भुत नज़ारे को शहर के प्रमुख स्थलों पर स्पीकर व एलईडी स्क्रीन के माध्यम से आमजन तक पहुँचाया गया, जिसका साक्षी पूरा प्रदेश बना।



राजभवन में 'एट होम'



15 अगस्त को राजभवन में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे के सानिध्य में एट होम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों और बड़ी संख्या में गणमान्यजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आगंतुकों से मुलाकात कर उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी व डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित मंत्रिमंडल सदस्य, सांसद, विधायक, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश, समाजसेवी, मीडिया प्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे।

सीमा पर जवानों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले की कोडेवाला बीएसएफ चौकी का दौरा कर जवानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जो बर्फीली वादियों से लेकर तपते मरुस्थल तक साहस और मुस्तैदी से देश की सुरक्षा कर रहा है और तस्करी व घुसपैठ जैसी गतिविधियों को नाकाम बना रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जवानों को बधाई दी और 1971 युद्ध में बीएसएफ की ऐतिहासिक भूमिका का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ द्वारा सामाजिक सरोकार, नशे व कुुरीतियों के खिलाफ जागरूकता और पौधारोपण जैसे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कोडेवाला पोस्ट पर एंटी-ड्रोन सिस्टम और रक्षा उपकरणों का अवलोकन किया एवं जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। ■



पर्यावरण पर ई-वेस्ट का प्रहार जागरूकता व सही प्रबंधन ही उपचार



- अरविंद कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ अभियंता
मोहित जैन, सहायक जनसंपर्क अधिकारी



हमारे जीवन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर उन्नत औद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों तक भारत की 'विकसित भारत' की ओर यात्रा में अपना अपूर्व योगदान दे रहे हैं। इन्हीं उपकरणों के सहयोग से भारत आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में नित नए आयाम छू रहा है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बढ़ती इस निर्भरता और उनके तेजी से पुराने हो जाने के कारण ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) की मात्रा भी लगातार बढ़ती है। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है, दुनिया के शीर्ष ई-वेस्ट उत्पादकों में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का स्थान तीसरा है। यहां हर साल हजारों टन ई-वेस्ट उत्पन्न होता है, जिसका सही तरीके से निस्तारण न होने के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

क्या है ई-वेस्ट?

ई-वेस्ट उन सभी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहा जाता है, जो अपने जीवनचक्र के अंत में पहुंच चुके होते हैं। ये उपकरण या तो पुराने हो गए हैं, टूट-फूट गए हैं या फिर तकनीकी परिवर्तन होने के कारण उन्हें नए मॉडल्स से बदल दिया गया है। इसमें बड़े घरेलू उपकरण जैसे वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टीवी से लेकर छोटे उपकरण जैसे मोबाइल फोन, चार्जर, कीबोर्ड, यूएसबी ड्राइव और सीडी प्लेयर शामिल हैं।

मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव

खराब इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणों को आमतौर पर लोग कबाड़ी द्वारा घरेलू कचरे के साथ निस्तारित कर देते हैं, जिससे ई-वेस्ट अनाधिकृत व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। इनके द्वारा ई-वेस्ट को गैर-वैज्ञानिक, रूढ़िवादी तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। ई-वेस्ट में हानिकारक धातुएं जैसे-सीसा/पारा, निकल, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसे कई प्रकार के विषैले रसायन मौजूद होते हैं। अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ई-वेस्ट को जलाने अथवा एसिड से धोने पर हानिकारक धातुएं एवं विषैले रसायन वायु एवं जल के साथ प्रवाहित व उत्सर्जित होकर मिट्टी, जल एवं वायु को दूषित करते हैं। ये प्रदूषक तत्व खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों एवं कैंसर जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं।

भारत में ई-वेस्ट की स्थिति

वैश्विक स्तर पर भारत ई-वेस्ट के उत्पादन में शीर्ष तीन देशों में शामिल है (चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद)। वर्ष 2024 में राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत में पिछले पांच वर्षों में ई-वेस्ट के उत्पादन में भारी वृद्धि देखी गई है, जो 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में ई-कचरे की समस्या सबसे



अधिक देखी जा रही है। भारत में ई-वेस्ट के बढ़ते दबाव को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 व 2024 लाए गए हैं। इसके तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), ई-वेस्ट के वैज्ञानिक पुनः उपयोग, रीसाइकल और रीफर्बिशिंग के महत्व, चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाने आदि जैसे विषयों पर जोर दिया गया है, ताकि उद्योगों द्वारा ई-वेस्ट से उत्पन्न पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके।

मूल्यवान भी हैं ई-वेस्ट

ई-वेस्ट में हानिकारक मेटल्स के अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम जैसी मूल्यवान धातुएं भी होती हैं। यदि ई-वेस्ट को अधिकृत ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा पुनः चक्रित किया जाए, तो न केवल हानिकारक एवं विषैले तत्वों के जल एवं वायु में उत्सर्जन को रोका जा सकता है, बल्कि इन मूल्यवान धातुओं की रिकवरी भी पर्यावरणीय अनुकूल विधियों द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ई-वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण से मूल्यवान धातुओं को पर्यावरण अनुकूल विधियां अपनाकर ई-वेस्ट से अलग कर, अतिरिक्त माइनिंग व अन्य प्रदूषक प्रक्रियाओं से भी बचा जा सकता है एवं उक्त प्रयास से 'सर्कुलर इकोनॉमी' को बढ़ावा भी मिलता है।

“प्रकृति का संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक महत्ती आवश्यकता है। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए हमें पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को अपनाना चाहिए जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और हम आगामी पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी एवं स्वच्छ धरा का उपहार दे पाएंगे।”

– मुख्यमंत्री



ई-वेस्ट के निस्तारण में राजस्थान की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रेरणादायी नेतृत्व में राजस्थान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। हाल ही में राज्य ने हरयालो राजस्थान महाभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ई-वेस्ट के निस्तारण में भी राज्य प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। 5 जून, 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने सात संभागीय मुख्यालयों व औद्योगिक शहरों में ई-वेस्ट संग्रहण के लिए 11 ई-वेस्ट संग्रहण वाहनों को रवाना किया। संग्रहण वाहनों द्वारा अब तक लगभग 147 टन ई-वेस्ट संग्रहित किया जा चुका है। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय-समय पर ई-वेस्ट से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, जैसे रीसाइक्लर्स, रिफर्बिशर्स एवं ई-कचरा पुनर्चक्रण उद्योग करने वाले उद्यमियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है।

जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका

ई-वेस्ट का स्थायी निपटान आवश्यक है, क्योंकि इसमें भारी धातुएं और विषैले रसायन होते हैं। हमारे घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नकारा, खराब इलेक्ट्रॉनिक-इलेक्ट्रिकल उत्पादों को कबाड़ी वाले, अनाधिकृत व्यक्तियों को न देकर, अधिकृत, रीसाइक्लर, कलेक्शन सेंटर्स पर सुपुर्द किया जाना चाहिए। जिससे ई-वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से अनुकूल विधियों द्वारा पुनः चक्रण कर मूल्यवान धातुओं की प्राप्ति की जा सके। इससे हम मानव स्वास्थ्य, सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति राजस्थान के प्रतिबद्ध प्रयासों को मजबूत करने की ओर इस महत्वपूर्ण कदम में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं।

ई-वेस्ट आधुनिक तकनीकी युग की एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई चुनौती है। इसके प्रभावी प्रबंधन के बिना यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गहन संकट बन सकता है। इसके निस्तारण व प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक दायित्व व नैतिक कर्तव्य है जिसमें उद्योग, समुदाय और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उपयोग को कम करने, उनकी जीवन अवधि बढ़ाने और अंत में उचित रीसाइक्लिंग को प्राथमिकता देनी होगी। ई-वेस्ट के प्रबंधन की दिशा में यही कदम हमारी भावी पीढ़ियों को एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर पाएगा। ■



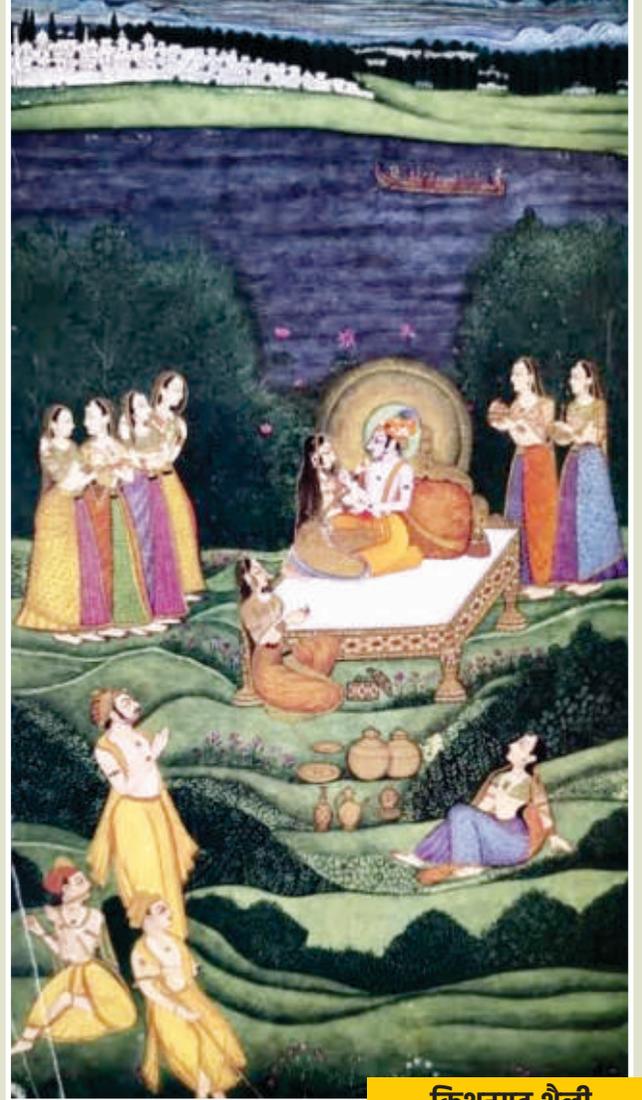


राजस्थानी चित्रशैलियों में वनस्पति चित्रण

– डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, चित्रकला विशेषज्ञ



बूंदी शैली



किशनगढ़ शैली

राजस्थानी चित्रकला अन्य भारतीय शैलियों से प्रभावित होती हुई स्वतंत्र रूप से राजस्थान के वीर प्रदेश में पोषित और पल्लवित हुई तथा वल्लभ और वैष्णव संप्रदाय में लीन हो गई। इसने शूरवीर राजाओं के हृदय पटल पर कृष्ण-राधा से जुड़े अपने ललित भावों की छटा बिखेरी। यही कारण रहा कि राजस्थान की लगभग प्रत्येक शैली में राधा-कृष्ण के विभिन्न रूपों एवं रस भावों का अंकन प्रमुखता से हुआ है। इसी रस भाव को चित्रों में मुखरित करने के लिए चित्रकारों ने प्रकृति को आधार बनाया।

राजस्थान में विभिन्न रियासतों में अलग-अलग शैलियों का विकास हुआ और शैली विशेष इसी रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका प्रमुख कारण यह

है कि इन शैलियों का कलात्मक विकास एक ही स्थान पर रुका नहीं, सदैव गतिशील रहा। संपूर्ण राजस्थानी चित्रकला को विभिन्न रियासतों के चित्रकारों ने अपनी-अपनी विशिष्ट शैली में चित्रित किया। अतः यह चित्र अपने स्थानीय प्रभाव व परंपराओं के कारण विभिन्न शैलियों में बंधकर सबके सामने आए। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण इसी प्रकार किया है और इसको चार भागों में बांटा तथा उनकी उपशैलियों को भी निर्धारित किया है-

1. **मेवाड़ शैली** – उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली
2. **मारवाड़ शैली** – जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली
3. **हाड़ती शैली** – कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली
4. **ढूंढाड़ शैली** – आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली, उनियारा शैली

यह सभी शैलियां और उप शैलियां अपने सौंदर्यात्मक लालित्य से भरी हैं। इनमें काव्य तत्व, चित्र तत्व तथा प्रकृति तत्व पूर्ण रूप से समाहित हैं। साथ ही धार्मिकता एवं श्रृंगारिकता दोनों राजस्थानी चित्रों के आधार बिंदु रहे हैं।

राजस्थानी शैली के चित्रों में उपर्युक्त वनस्पतियों एवं पेड़ों का चित्रण देखकर अनुभव होता है कि चित्रकारों का लक्ष्य केवल शैलियों के लिए मात्र



नाथद्वारा शैली

विषय के अनुरूप चित्रण करना ही नहीं था। चित्रकार जब श्री नाथ जी, राधा-माधव या अन्य किसी भी विषय पर चित्र बनाते थे, तब उन सभी का गहन अध्ययन करते थे, तब कहीं जाकर रंग-रेखाओं के साथ अपने राजाओं के मनोभाव उनकी भक्ति, उनके श्रृंगार सहित कैनवास पर अंकित करते थे। इस चित्रण में प्रकृति का वर्चस्व सर्वाधिक होता था। राजस्थान शूर वीरों की भूमि रही है, किंतु भक्ति और आध्यात्मिक विषय भी यहां की शैलियों में व्याप्त रहे हैं। इसलिए चित्रकारों ने अध्ययन-मनन के पश्चात विषय के अनुरूप चित्रण किया। उदाहरण के लिए मेवाड़ शैली की उप शैली नाथद्वारा शैली है, जिसे पिछवाई शैली भी कहा जाता है। इस शैली में विभिन्न प्रकार की पिछवाईयां श्री नाथजी की लीलाओं पर आधारित होती थीं, जो श्रीनाथजी के विग्रह के पृष्ठभूमि में वातावरण उत्पन्न करने के लिए लगाई जाती हैं।

प्रस्तुत चित्र में चित्रकारों ने प्रकृति को अत्यंत सुंदर ढंग से चित्रित किया है, जिससे श्रीनाथजी के बालरूप की भव्यता, विशालता उत्पन्न हो रही है। इसमें केले, आम, पीपल और अशोक आदि वृक्षों का चित्रण किया गया है। यह सभी अपनी विशेषताओं और प्राकृतिक विशालता के साथ श्रीनाथजी की महिमा को मंडित करते हैं। हरे रंग की विविधता को भी ध्यान में रखते हुए चित्रकार ने इन वृक्षों का चित्र में अंकन किया है। केले के वृक्षों की लयबद्धता को चित्र में बहुत ही सुंदर संयोजन के साथ अंकित किया गया है, जिससे श्रीनाथजी केंद्र बिंदु बने हुए हैं। दूर पृष्ठभूमि में आसमान में रंग-बिरंगे हल्के रंगों से बादलों को चित्रित किया गया है, जिससे अनंत भाव का बोध हो रहा है। इस रंग बिरंगे प्रकृति चित्रण में पक्षियों का भी चित्रण कर सौंदर्यात्मक भाव उकेरा गया है। श्रीनाथजी के हाथों में कमल पुष्प दिखाकर चित्रकार ने आध्यात्मिक संभावनाओं का बोध कराने का प्रतीकात्मक प्रयास किया है, जिससे दर्शक सौम्य भक्ति भाव का अनुभव कर आध्यात्मिक रासभाव का आनंद ले सकें। इस प्रकार पिछवाई कला से आध्यात्मिक भक्ति भाव का सहज ही अनुभव होता है।

मेवाड़ शैली में लगभग सभी चित्रों में प्रकृति के वर्चस्व को दिखाने के लिए विषय के अनुरूप पेड़ पौधों को चित्रकारों ने सजीवता से चित्रित किया है। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर सौंदर्य को और प्रभावशाली बनाया गया है।

मारवाड़ शैली की उपशैली किशनगढ़ शैली है, जिसमें पीढ़ियों से वल्लभ संप्रदाय की भक्ति समाहित थी, जिसको कलाकारों ने बखूबी अपने चित्रण का आधार बनाया। भक्ति भाव की सहज अनुभूतियों का प्रकृति के माध्यम से प्रतीकात्मक ढंग से चित्रण किया गया। इस प्रकार किशनगढ़ के सभी चित्रों को देखा जाए, तो वह प्रकृति का प्रतिफल ही हैं। इनमें सफल चित्रण से प्रकृति स्वयं आध्यात्मिक हो उठी है। इसका हर वृक्ष जगमग कर उठा है। संपूर्ण चित्र चेतना से भर उठा है जैसे तांबूल सेवा इस चित्र में कृष्ण- राधा को विशाल प्रकृति के कुंज के मध्य पान खिलाते हुए असीम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। समय और साथ में सखियों और शाखाओं को भी दर्शाया गया है। इस चित्र में स्पेस को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। संपूर्ण चित्र में हरे रंग की विविधता का अंकन किया गया है, जो प्रफुल्लता और शांति का प्रतीक है। इस चित्र की अग्र भूमि में छोटे-छोटे पौधों के साथ गेंदा, चमेली आदि पुष्पों को चित्रित किया गया है, जिससे संयोजन में एक लयबद्धता दिखाई देती है। पृष्ठभूमि तक जाते-जाते आम, अशोक आदि विशाल पेड़ों को चित्रित किया गया

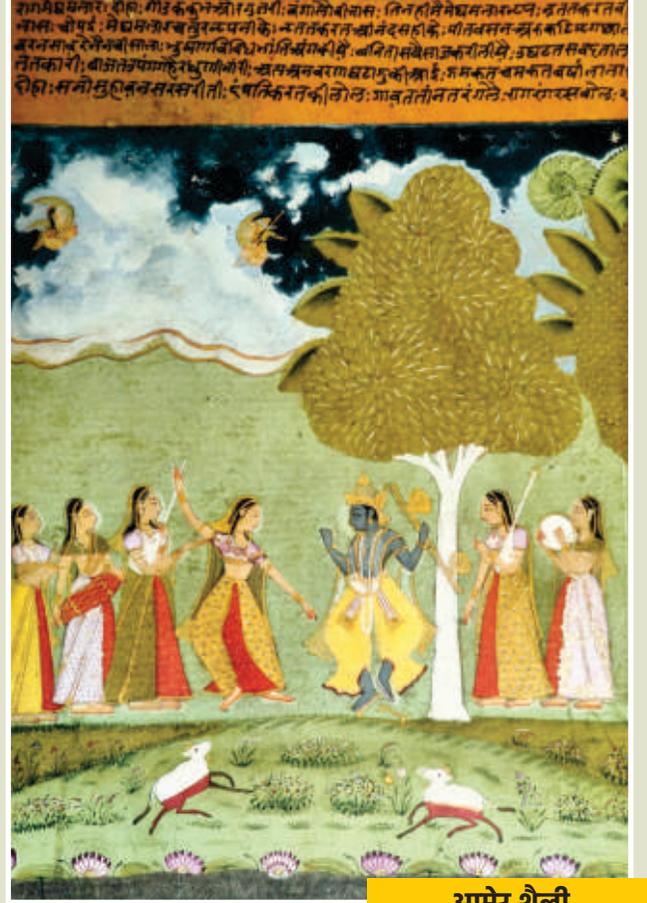
है जो सुकून और निर्मल पर्यावरण की अनुभूति करवाता है। चित्र भक्ति भाव से पूर्ण है। मध्य में जलाशय गहरे नीले रंग का दिखाया गया है, जिसमें कमल पंखुड़ियों को खिलते हुए दर्शाया गया है, जो चित्र में एकात्मभाव का बोध कराता है। पृष्ठभूमि में श्वेत महलों के साथ ही शमी और अशोक के वृक्षों को संयोजित किया गया है। बादलों को भी हल्के रंग से चित्रित किया गया है। सखी और सखाओं को चित्र के केंद्र में बैठे राधा-कृष्ण को मुख्य बिंदु मानकर उन्हीं की ओर मुखरित होता हुआ दिखाया गया है।

इस चित्र के साथ किशनगढ़ के अन्य चित्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वृंदावन के कुंजन को ही चित्रित कर दिया गया हो। प्राकृतिक खुले वातावरण के चित्रण को कुछ लोगों ने मुगल प्रभाव बताया है, किंतु यह सर्वथा सत्य है की भक्ति बंधन में नहीं बंधती, उसे विस्तार चाहिए, खुले आकाश की छाया चाहिए, वह प्रकृति के समान असीम है, उसका कोई ओर-छोर नहीं है। इस शैली की भक्ति छः-सात पीढ़ियों का कमाया हुआ पुण्य है। प्रस्तुत चित्र में राधा माधव के भाव एवं रूप वर्णन के साथ-साथ पल और क्षणों को भी चित्रित किया गया है, जो प्रकृति की ही रूप माधुरी है। इन चित्रों में यदि प्रकृति चित्रण हटा दिया जाए तो अध्यात्म का भाव भी समाप्त हो जाएगा। आस-पास केले के वृक्षों को चित्रित किया गया है। सर्वत्र हरे रंग का प्रभाव व्याप्त है। इस प्रकार किशनगढ़ के चित्रों में प्रकृति स्वयं लास्य नृत्य करती प्रतीत होती है।

हाड़ौती शैली की बूंदी उपशैली है। अपनी विशेषताओं के कारण विश्व फलक पर अपना विशेष महत्व रखती है। काव्य, साहित्य और प्रकृति प्रेमी राजाओं के आश्रय में बूंदी शैली अधिक विकसित हुई, इसीलिए प्राकृतिक दृश्य, विशेषकर पेड़ पौधों आम, केला, कदंब, पीपल, फूलों की बेल, पक्षियों, तालाब और नदियों को भी चित्रित किया गया है। राधा - कृष्ण की पूजा करते हुए प्रस्तुत चित्र में चित्रकार ने विशाल संयोजन को फलक पर गढ़ दिया है। अग्र भूमि में जलाशय दिखाया गया, जिसमें एक विशाल नाव, राधा-कृष्ण और गोपियों को दिखाया गया है। पवित्रता, भव्यता, शांति को दर्शाने के लिए अशोक, आम, कदंब के वृक्षों और खिले हुए पुष्पों से एकात्मभाव को चित्रकार ने चित्र में मानो बिखेर दिया हो। अन्य पशु पक्षियों को बहुत ही प्रमुखता से चित्रित किया है। केले के वृक्ष और गेदे के पुष्पों को संयोजन के अनुसार चित्रित किया गया है।

केले के वृक्षों को दोनों तरफ स्तंभ के रूप में अंकित किया गया है, जो भक्ति भाव की अनुभूति को साकार कर रहे हैं। मध्य भाग में राधा कृष्ण की पूजा करते हुए राजा को दिखाया गया है। अन्य विवरणों में सखी वाद्य यंत्रों के साथ चित्रित की गई है। पशु-पक्षियों के विभिन्न क्रियाकलाप भी चित्रित किए गए हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति जब फलीफूली होती है तो हर जीव जंतु स्वतंत्र हो आनंद का अनुभव करता है। पृष्ठभूमि में दोनों तरफ महल दिखाए गए हैं और आकाश में नीले धूसर (ग्रे) रंग का अंकन किया गया है, जहां से देवतागण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वहीं, आम, आंवले, बरगद, पीपल को अंकित कर चित्र की विशालता को रंग और रेखाओं के माध्यम से अंकित किया गया है। बूंदी चित्र शैली में प्राकृतिक उपादानों का विशेष महत्व रहा है। विशाल पेड़-पौधों के चित्रण से प्रेम, संपन्नता, सौम्यता, स्थायित्व, विशालता, ये सभी चित्र में प्रकृति के होने मात्र से ही चित्र की आत्मा मुखरित हो चेतनामय हो उठी है।

ढूंढाड़ शैली की आमेर उपशैली है। इस शैली के प्रकृति चित्रण में भी



आमेर शैली

चित्रकारों ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अंकन किया है, जैसे केले, खजूर, आम, आंवला, कुमुदिनी, कमल, विभिन्न प्रकार की पुष्प बेलों का भी चित्रण किया गया है। प्रस्तुत चित्र राग मेघ मल्हार में चित्रकार ने पुरुष राग का चित्रण किया है। यह राग वर्षा, मानसून से जुड़ा हुआ है। इसमें कदंब वृक्ष के नीचे राधा-माधव को उन्मुक्त भाव से नृत्य करते हुए दिखाया गया है। साथ ही पांच मित्र रागनियां चित्रित हैं, जिनके हाथों में वाद्य यंत्र हैं। यह राग वर्षा ऋतु, मानसून से जुड़ी हुई है। अग्रभूमि में कमल पुष्प का चित्रण किया गया है। इसी चित्र में कदंब, खजूर, केले के वृक्षों का चित्रण किया गया है। इसमें हल्के हरे रंगों की विभिन्न टोन्स प्रयोग किए गए हैं। पृष्ठभूमि में गहरे नीले और सफेद रंगों से पानी से भरे मेघों को अंकित किया गया है। इस प्रकार चित्र में ताजगी भरे हरे रंगों का प्रयोग चित्रकार ने विषय का महत्व और गरिमा बढ़ाने के लिए किया है।

इस प्रकार राजस्थानी लघु चित्रों के चित्रकारों ने अपने चित्रों में सामान्य रूप से प्रकृति का चित्रण नहीं किया है, बल्कि गहन अध्ययन के पश्चात चित्रों में भक्ति शृंगार, राग-रागिनियों, युद्ध, विहार आदि जैसे विविध विषयों के अनुरूप ही वनस्पतियों को चित्रित किया है। इससे राजस्थानी लघु चित्र संपूर्ण विश्व में आज भी तरोजा हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक दिशा भी हैं, क्योंकि इन चित्रों में चित्रित हर पेड़-पौधे हमारे वेद पुराणों में विशेषताओं के साथ वर्णित हैं। पर्यावरण संरक्षण और उसका आनन्द हमारी ललित कलाओं में, जन जीवन में हमेशा से रहा है। ■

प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में खुले बर्तन बैंक

– सुश्री संतोष कुमावत, सहायक निदेशक



राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव और प्रभावी पहल करते हुए 'बर्तन बैंक योजना' की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक मुक्त आयोजनों को बढ़ावा देना है। यह पहल न केवल स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण का भी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार की यह योजना अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन सकती है।

एक लाख रुपए मूल्य के स्टील बर्तन, पहला बैंक खैराबाद में

वर्ष 2025-26 के बजट के अंतर्गत पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों को एक-एक लाख रुपये मूल्य के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं। इन बर्तनों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया। अब प्रदेश की सभी चिह्नित 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जा चुके हैं। यह पहल ग्रामीणों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है। राज्य के 13 जिलों की 30-30 चयनित ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक बर्तन बैंक खोले गए हैं।

- न्यूनतम 400 बर्तन सेट, प्रत्येक बर्तन सेट में 6 आइटम
 - प्रत्येक बर्तन सेट में 1 थाली, 3 कटोरी, 1 चम्मच व 1 गिलास शामिल हैं
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 400 बर्तन सेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से एक विशेष रैक में रखा गया है। यदि किसी बर्तन की

टूट-फूट या गुम होने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका मूल्य उपयोगकर्ता को देना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सेट के लिए 3 रुपए प्रति उपयोग किराया निर्धारित किया गया है।

संचालन और निगरानी

बर्तन बैंकों का संचालन राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इनके चयन की प्रक्रिया 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा संपन्न किया गया है। इस समिति में शामिल हैं:-

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- अधिशासी अभियंता, जिला परिषद
- जिला परियोजना समन्वयक (राजीविका)

प्लास्टिक मुक्त गांव की ओर एक सार्थक पहल

राज्य सरकार की यह योजना केवल प्लास्टिक उपयोग को कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय संकट प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या और जलवायु परिवर्तन के खतरे को भी कम करने की दिशा में एक प्रयास है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण जनता को ऐसे व्यावहारिक विकल्प प्रदान किए जाएं, जो उन्हें प्लास्टिक से मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। ■

संरक्षित पहाड़ समृद्ध शहर

– विनय सोमपुरा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

किसी भी क्षेत्र का समेकित और दूरदर्शी विकास तभी संभव है, जब यह विकास प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखते हुए किया जाए। इसी उद्देश्य के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में 7 साल बाद नई हिल पॉलिसी लागू की गई है, जो नगरीय सीमा में आने वाले पहाड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। 'मॉडल विनियम-2024' के नाम से लागू यह नीति न केवल राजस्थान की पारिस्थितिकी को सुरक्षित करेगी, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए हरित और संतुलित वातावरण की नींव भी रखेगी।

पहाड़ियां-मनोरम दृश्यावली से आगे, जन-जीवन में रची-बसी

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्थित पहाड़ियां केवल प्राकृतिक दृश्यावलियों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, जैव विविधता, स्वच्छ वायु और सांस्कृतिक-आध्यात्मिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तीव्र शहरीकरण और अनियंत्रित विकास कार्यों के कारण इनका अस्तित्व संकट में पड़ गया था। वर्ष 2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुरानी हिल पॉलिसी को निरस्त कर दिया था। इसके बाद से एक सशक्त हिल पॉलिसी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में नई हिल पॉलिसी जारी की है, जो माउंट आबू डेको-सेंसिटिव जोन को छोड़कर पूरे राज्य के अधिघोषित नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

15 डिग्री से अधिक ढलान वाली पहाड़ियों पर निर्माण निषेध

नई नीति के अन्तर्गत पहाड़ियों को ढलान के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

श्रेणी 'अ' (8 डिग्री तक का ढलान)

इस क्षेत्र में मास्टर प्लान में अनुज्ञेय उपयोगों के अनुरूप भू-उपयोग परिवर्तन एवं निर्माण की अनुमति होगी। प्रचलित भवन विनियम व टाउनशिप पॉलिसी के तहत निर्माण अनुमत होगा।

श्रेणी 'ब' (8 से 15 डिग्री तक का ढलान)

संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यहां निम्न घनत्व वाली गतिविधियां सशर्त अनुमत हैं, जैसे फार्महाउस, रिसॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर, कैम्पिंग साइट्स, सौर ऊर्जा संयंत्र। वहीं आवश्यक सार्वजनिक उपयोग जैसे विद्युत व जल आपूर्ति भी सीमित घनत्व में अनुमत होंगे। विशिष्ट मामलों में राज्य सरकार अन्य उपयोग भी अनुमत कर सकती है।

श्रेणी 'स' (15 डिग्री से अधिक का ढलान)

इस श्रेणी में किसी भी प्रकार का निर्माण या अन्य गतिविधियां अनुमत नहीं होंगी। केवल सीमित सार्वजनिक उपयोग ही सशर्त अनुमत होंगे।

जल संरचनाओं और बफर जोन का विशेष संरक्षण

श्रेणी 'ब' और 'स' क्षेत्रों में जल स्रोतों के बफर जोन को लेकर विशेष



प्रावधान किए गए हैं। 10 मीटर से अधिक चौड़ाई वाली नहरों, नालों और स्टॉर्म वाटर ट्रेनों के किनारे 9 मीटर का बफर अनिवार्य होगा। छोटे जल निकायों या बावड़ियों के चारों ओर 6 मीटर का बफर जोन तय किया गया है। जिन जलाशयों की सीमा निर्धारित नहीं है, वहां सिंचाई विभाग द्वारा सीमा तय की जाएगी। संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान झील संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015 और पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचनाएं भी इस नीति में मान्य होंगी।

सामान्य शर्तें व अनिवार्य प्रावधान

- श्रेणी 'ब' क्षेत्रों में प्रस्तावित क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत भाग स्थानीय वृक्षों से सघन वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करना होगा।
- जल-मल निस्तारण के लिए बायो-डाइजेस्टर प्रणाली अनिवार्य होगी।
- निर्माण के समय प्राकृतिक नालों को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकेगा।
- सड़क, पार्किंग व अन्य अधोसंरचनाओं के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई

- निर्माण मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा।

- आवश्यकता पड़ने पर निर्माण को रोकना या ध्वस्त किया जा सकता है।
- पुनर्भरण राशि निर्माणकर्ता से वसूली जाएगी।
- पूर्व में दी गई स्वीकृति को निरस्त किया जा सकता है।
- यदि अनुमति से पूर्व किसी भी प्रकार की कटिंग या फिलिंग की गई हो, तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- पंजीकृत तकनीकीविदों द्वारा अनुचित कार्य या जानकारी छिपाने पर पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
- नगरीय निकाय द्वारा दी गई भवन स्वीकृति स्वामित्व का प्रमाण नहीं मानी जाएगी। विवादित भूमि पर दी गई अनुमति के लिए निकाय जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रकृति के साथ विकास का संतुलन

राजस्थान सरकार की यह नई हिल पॉलिसी न केवल पहाड़ियों को भूखंड के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति को रोकती है, बल्कि उन्हें सार्वजनिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने का ठोस प्रयास है। इससे शहरी प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु संतुलन और नगरीय सौंदर्य में सुधार होगा। यह नीति नगरीकरण की चुनौतियों के बीच प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए स्थायी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक दूरदर्शी और निर्णायक कदम है। ■

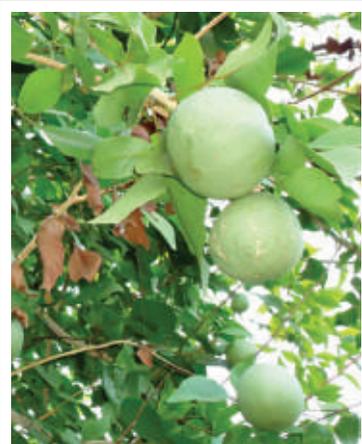
गुंदा, खेजड़ी, बेर, सांगरी के साथ मरुस्थल से निकली सेहत की बात

- डॉ. अंजलि फाटक, न्यूट्रिशनिसट

राजस्थान के देशज पौधों में छिपा है स्वास्थ्य और पोषण का खजाना

राजस्थान की रेतीली धरती केवल मरुस्थलीय विस्तार ही नहीं है, बल्कि इसने अपने में पोषण, औषधीय गुणों और पारंपरिक ज्ञान की अद्भुत धरोहर को भी संजोए रखा है। कम वर्षा (300-400 मिमी), तीक्ष्ण तापमान (48 डिग्री सेन्टीग्रेट और अधिक तक) और क्षारीय-रेतीली मिट्टी जैसी कठिन जलवायु में भी यहां की विविध वनस्पति न केवल जीवन्तता की परिचायक है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए अमूल्य उपहार प्रदान करती है।

राजस्थान में मूल रूप से पाए जाने वाले पौधे जैसे केर, सांगरी, खेजड़ी, गुंदा, बेर, बेल आदि में प्राकृतिक पोषक तत्व, औषधीय गुण और डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे काजरी, जोधपुर और आईसीएआर-आईआईएमआर, हैदराबाद के शोधों ने भी इन पौधों को सुपरफूड्स की श्रेणी में रखा है।





राजस्थान के पोषक तत्वों से युक्त प्रमुख पौधे व उनके लाभ

- **केर (Capparis decidua)**

मरुस्थल का अमृतफल

पोषण: विटामिन बी, प्लेवोनॉयड्स, फाइबर

लाभ: पाचन में सहायक, कब्ज में राहत, एंटीऑक्सीडेंट

उपयोग: अचार, सूखी सब्जी

- **सांगरी (Prosopis cineraria)**

राजस्थान का कल्पवृक्ष

पोषण: प्रोटीन (12-15%), आयरन, कैल्शियम

लाभ: हड्डियों की मजबूती, मधुमेह नियंत्रण

उपयोग: केर-सांगरी सब्जी

- **गुंदा (Cordia myxa)**

चिपचिपा पर पौष्टिक

पोषण: पेक्टिन, फाइबर, विटामिन बी

लाभ: कोलेस्ट्रॉल कम करना, आंतों की सफाई

- **बेर (Ziziphus mauritian)**

देसी टॉनिक

पोषण: पोटैशियम, विटामिन सी, फाइबर

लाभ: तनाव व अनिद्रा में राहत, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि

- **कुमटिया बीज व फालसा**

छिपे पोषण रत्न

कुमटिया बीज: ओमेगा-3 फैटी एसिड, हृदय स्वास्थ्य

फालसा: विटामिन सी व आयरन का स्रोत, एनर्जी ड्रिंक

- **सीताफल (Annona squamosa)**

अरावली का मीठा उपहार

पोषण: विटामिन बी6, मैग्नीशियम

लाभ: मस्तिष्क व हड्डियों के लिए फायदेमंद

- **बेल (Aegle marmelos)**

धार्मिक और औषधीय

पोषण: विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन

लाभ: पेट रोगों में लाभकारी, शुगर कंट्रोल

- **अन्य पोषक पौधे**

आंवला: विटामिन सी का भंडार, एंटी-एजिंग

ग्वार फली: फाइबर से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रक

मोठ, मूंगफली, तिल: प्रोटीन, हेल्दी फैट और मिनरल्स के बेहतरीन स्रोत

वैज्ञानिक पुष्टि और पारंपरिक ज्ञान का संगम

इन पौधों का पारंपरिक उपयोग राजस्थान के ग्रामीण जीवन में पीढ़ियों से चला आ रहा है-जैसे प्रसवोत्तर महिलाओं के लिए केर-सांगरी, गर्मियों में बेल शरबत, बालों व त्वचा के लिए आंवला इत्यादि। अब आधुनिक विज्ञान भी इन उपयोगों की पुष्टि कर रहा है। आईसीएमआर, सीएसआईआर और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए शोध बताते हैं कि इन पौधों में फाइटोकेमिकल्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण, और फ्री रेडिकल्स को समाप्त करने की क्षमता होती है, जिससे ये हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, मोटापा जैसी बीमारियों के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा कवच बनाते हैं। ■



व्याघ्र गाथा

मैं सरिस्का हूँ ...

- राजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त पीसीसीएफ

मैं अरावली की देश की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में बसा हूँ, जो लगभग 2 अरब वर्ष पहले प्रोटेरोजोइक कल्प (प्री-केम्ब्रियन युग) में बनी थीं। आइए, मैं इतिहास की तहों से झांकते हुए आपको अपनी महिमा, पतन, संघर्ष और सफलता की यात्रा पर ले चलता हूँ। मेरी वह यात्रा, जिसमें 2008 से 2025 के 17 वर्षों में मैं शून्य से 48 बाघों की शरणस्थली तक पहुंचा।



पद्मश्री श्री कैलाश सांखला

मेरे जंगलों ने व्यक्तियों और संस्थाओं के जीवन को निर्णायक मोड़ दिए हैं। पद्मश्री श्री कैलाश सांखला ने जब सरिस्का के माधोगढ़ क्षेत्र में एक बबूल के मचान से अपने जीवन में पहली बार बाघ का शिकार किया, तो वे गहरे पछतावे से भर उठे। अपराधबोध में उन्होंने बाघ के शरीर को स्पर्श किया, उससे क्षमा मांगी और यह संकल्प लिया कि अब जीवन भर वे बाघों की रक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित रहेंगे। 2005 की विपत्ति ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रबंधन की दिशा बदल दी और अन्य बाघ अभयारण्यों को बचाने का अवसर प्रदान किया।

भारत में 1 अप्रैल 1973 को 'प्रॉजेक्ट टाइगर' की शुरुआत हुई और इसके प्रथम निदेशक के रूप में श्री कैलाश सांखला नियुक्त किए गए। बाघ संरक्षण की दिशा में उनके द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना एक मील का पत्थर सिद्ध हुई।



हर वर्तमान विद्यमान की तरह मैं अतीत का अवशेष हूँ। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास मत्स्यराज विराट की नगरी और पांडुपोल के इन्हीं जंगलों में बिताया था। मेरे भीतर कांकवाड़ी और भानगढ़ के किले, सरिस्का पैलेस और शिकार-ओधियों में मुगलों और महाराजाओं का मध्यकालीन इतिहास छिपा है। अकबर और जहांगीर मेरे वन्य क्षेत्र में बाघ और तेंदुए के शिकार करने आए। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मेरे हृदय में स्थित कांकवाड़ी किले में निर्वासित रखा।

मैं अलवर रियासत का हिस्सा था और शिकार-आरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाता था। मैंने बाघ और तेंदुओं को अपने वितान में संजोया और संरक्षित किया। मैं देश में बाघ वितरण की पश्चिमी सीमा हूँ। मेरे शासकों ने भी मुझे एक अलग शिकारखाना और शिकार पलटनों के जरिये सुरक्षित रखा। अंग्रेजों को भी मेरे क्षेत्र में बाघ और तेंदुओं का शिकार करने के लिए आमंत्रित किया गया। सिरावास, सिलिसेढ़, खोह, अजबगढ़, रामपुर, नरैनपुर और अकबरपुर में शिकार के ब्लॉक आरक्षित किए गए, जहां भरतपुर के डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा महीने के दूसरे पखवाड़े में केवल 95 रुपये में बाघ और 55 रुपये में तेंदुआ मारने की अनुमति दी जाती थी। निःशब्द प्राणियों, नर, मादा और शावक, सबको गोलियों से भेदा जाता, कभी-कभी तो पूरा परिवार ही मिटा दिया जाता था। कैसा खेल था यह, जिसमें सारे नियम शिकारी के पक्ष में थे! सरिस्का की मिट्टी पर हुए अपराधों के कोलाहल में मैं मौन रोता रहा।

मेरे धोक और खैर के जंगलों को बार-बार तथाकथित 'प्रबंधन' के नाम पर उजाड़ा गया। असली उद्देश्य केवल वन-राजस्व बढ़ाना था। 1900 से पहले तक मुझे रूथ (घास आरक्षित क्षेत्र) और बनियां (ईंधन और शिकार संरक्षित क्षेत्र) विभागों के अंतर्गत रखा गया था। अलवर राज्य के पहले वन अधिकारी

एफ.एल. कूम्ब्स के अधीन 1903 में इन विभागों को मिलाकर वन विभाग बना। उन्होंने कार्य योजनाएं बनाईं और चयन पद्धति से इमारती लकड़ी तथा कॉपिस विड स्टैंडर्ड्स (सीडब्ल्यूएस) पद्धति से ईंधन लकड़ी काटने की व्यवस्था दी। बाद में इस प्रणाली को संस्थागत रूप दिया गया, जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 15 से 20 धोक वृक्ष बीज वाहक के रूप में छोड़े जाते, ताकि अंकुरण सुनिश्चित हो और कटाई से थक चुके वृक्षों की जगह ले सकें। वार्षिक कूपों को अधिकारी और कर्मचारी चिन्हित करते, जिन्हें ईंधन, कोयला और कत्था हेतु निजी ठेकेदारों से कटवाया जाता। इस शोषण ने मेरे श्रेष्ठ और सुलभ जंगलों को बुरी तरह नष्ट किया।

मेरे हरित वनों को कुल्हाड़ी से तभी राहत मिली जब 1970 के दशक के बाद परिस्थितियां बदलीं, यद्यपि मुझे वर्ष 1955 में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संरक्षित घोषित कर दिया गया था और वर्ष 1958 में अभयारण्य घोषित किया गया। वर्ष 1978 में मुझे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ अभयारण्यों की सूची में शामिल किया गया, जबकि रणथंभौर समेत मेरे भाग्यशाली नौ साथी वर्ष 1973 में ही जुड़ चुके थे। मेरे प्रबंधकों का कहना था कि तांबे की खदान की संभावनाओं ने शुरुआती चरण में मेरी शामिलीकरण में देरी कर दी। वर्ष 1972-73 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए 9 बोरहोल परीक्षणों ने यह सिद्ध किया कि धातुकर्म आर्थिक नहीं है और इस तरह मेरा खजाना बच गया। आज मैं राजस्थान के सबसे घने वनों में से एक के साथ फल-फूल रहा हूँ।

मैंने उच्च वर्ग और आमजन दोनों को अपने ईश्वरीय सौंदर्य की सराहना





करते देखा, पर मुझे कभी भी रणथंभौर जैसी महत्ता नहीं मिली। शायद इसका कारण था-गहरे वनों में बसे गांवों से उत्पन्न मानवीय हस्तक्षेप के चलते बाघों का कम दिखना। रणथंभौर की यह पीड़ा 1976 में 12 गांवों के पुनर्वास के जरिये दूर हुई। वर्ष 1966-67 में मेरे भीतर कालिघाटी और स्लोपका गांव पुनर्वसित किए गए और 1976 में करनकवास व किरास्का को बंदीपुल, डुलावा और सिरावास में स्थानांतरित किया गया। पर मेरी खुशी क्षणिक रही, क्योंकि कई पुनर्वसित परिवार लौटकर कुंडालका के पास बस गए और नया कुंडालका गांव बसा लिया। इसने अगले 31 वर्षों तक मेरे संरक्षण प्रयासों को झटका दिया। 2007 में भगानी गांव का पुनर्वास हुआ। आज भी मेरे भीतर 26 गांव बसे हुए हैं, जो अपने जीवनयापन के लिए मुझ पर दबाव डालते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें भी उतना ही अधिकार है, जितना जंगली प्राणियों को। पर मेरे नए रक्षक उन्हें स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि बाघों की प्रजनन दर बेहतर हो रही है।

मेरे निर्मल अरण्यों में अनेकों बाघ माता-पिता और उनके शावक विचरते थे। यह उनके लिए स्वर्ग था, भरपूर शिकार और पौष्टिक अनोगेसियस, कैपेरिस और जिजिफस की पत्तियों से समृद्ध। मैं उन बाघ अभयारण्यों में गिना जाता था, जहां शिकार घनत्व सबसे अधिक था। परन्तु वर्ष 2002 से 2004 तक, शिकारी मेरी सीमाओं से घुस आए और बाघों को एक-एक करके मार डाला, यहां तक कि वर्ष 2004 तक मेरी पूरी बाघ आबादी समाप्त हो गई। पहले उन्होंने परिधि में बाघ और तेंदुओं को मारा और फिर कालिघाटी-मलाजोरका पठार तक पहुंचकर अंतिम बाघ को समाप्त किया। वे 5-10 के समूह में आते और लोहे के फंदे लगाते। रात को जब फंसा हुआ बाघ दहाड़ता, तो पेड़ों से उतरकर उसके मुंह में गोली मारते, ताकि खाल को नुकसान न पहुंचे और अच्छी कीमत मिले। तेंदुओं को सिर पर लाठियों से पीटकर मारा जाता। मेरी घाटियों में गोलियों की गूंज सुनाई देती रही, पर मेरे रक्षकों ने ध्यान नहीं दिया और धीरे-धीरे मैंने अपने सारे धारीदार फरिश्ते खो दिए। यहां तक कि वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिक और प्रशिक्षु, जो हर वर्ष मुझमें अभ्यास करते थे, वे भी समय पर चेतावनी नहीं दे पाए। संरक्षणवादियों ने मेरे दुःख को “टाइगरलेस सरिस्का, सरिस्काराइजेशन, पोचर्स पैराडाइज” जैसे शब्दों में अभिव्यक्त किया। मेरे रक्षकों की लापरवाही और गाँववालों के लालच व प्रतिशोध ने मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कलंकित किया।

नवंबर 2004 से जून 2008 तक के अंधकारमय दिन मैंने पीड़ा में बिताए, अपनी महिमा की ऊंचाई और पतन की गहराई को याद करते हुए। फिर एक समर्पित टीम आई, जिनमें मुझे आशा की किरण दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने स्वयं अपने दूत भेजे हैं। अचानक मेरे क्षेत्र में हलचल बढ़ गई। अधिकारी और कर्मचारी रात में पैदल व वाहनों से सर्चलाइट के साथ गश्त करने लगे। सीमावर्ती गांवों में बार-बार छापे पड़े, शिकारियों की गिरफ्तारी हुई, सुरक्षा ढांचा सुदृढ़ हुआ और अब तेंदुए मेरे साम्राज्य के शासक बनकर विचरने लगे। मेरे शाकाहारी जीवों के लिए चारा भरपूर था, जिसके चलते सांभर की संख्या बढ़ी और बड़े शिकार की उपलब्धता में वृद्धि हुई। समर्पित वैज्ञानिक ए.जे.टी. जॉन सिंह, जो हर साल वन्यजीव संस्थान से आते, कहा करते-“सांभर संरक्षण ही बाघ संरक्षण है।”

साढ़े तीन वर्षों के अंतराल के बाद, मैंने नया उत्साह देखा। नया पानी में दो 1 हेक्टेयर के बाड़े बने। पहली बार हेलिकॉप्टर मेरे क्षेत्र में उतरे और 28 जून 2008 को दोपहर 1:13 बजे, बारिश की फुहारों के बीच एमआई-17 हेलिकॉप्टर मेरे क्षेत्र में उतरा और बाघ संरक्षण के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित कार्गो लेकर आया। राजा ने अपने खोए साम्राज्य में कदम रखा और मेरे जंगलों में उल्लास गूंज उठा। सांभर, चीतल और लंगूरों की चेतावनी पुकारें तेज हो गईं। मेरी घाटियां गूंज उठीं। शोक गीत अब उल्लास के गीत बन गए। बारिश की बूंदों के साथ मेरी आंखों से आंसू बहे, क्योंकि उस दिन, सरिस्का फिर जीवित हो उठा।

मगर पीड़ा ने दोबारा दस्तक दी। 14 नवंबर 2010 को, पहला नर बाघ ST-1, जिसने मेरे जंगलों में मुस्कान लौटाई थी, जहर देकर मार दिया गया। इससे पुनर्वास कार्यक्रम को झटका लगा। पर कुछ समय बाद मैं संभल गया और कार्यक्रम चलता रहा। अब तक रणथंभौर से 11 बाघ मेरे यहां लाए जा चुके हैं। हालांकि मैंने कुछ शावक और वयस्क खो भी दिए, पर मैं अब भी 48 बाघों के साथ फल-फूल रहा हूँ। शोधकर्ताओं का कहना था कि मानवीय दबाव और तनाव ने यहां की मादाओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित किया था, परंतु अब मेरे यहां ऐसी कोई शिकायत नहीं रही। अब मेरी समकक्ष पत्ना ने भी 2009 में पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू किया, और वहां के बड़े निर्जन क्षेत्र ने 16 वर्षों में आबादी 75 से अधिक कर दी।

मेरा सपना है कि बाघिन माताओं के प्रसव हेतु मेरे कोर क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़े। चार शावकों के जन्म का मेरा सपना पूरा हो चुका है। मेरी बाघिनें ST-12, ST-22 और ST-19 ने 4-4 शावक जन्मे हैं-यह इतिहास मेरे आंगन में बना। अब मैं 48 से 50 तक की वहन क्षमता बढ़ते देखने का स्वप्न संजोए हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे कोर क्षेत्रों से गांव पुनर्वसित हों और लोग मेरी सीमाओं से बाहर सुरक्षित आजीविका पाते हुए बेहतर जीवन जिएं। ■

मुझे खुशी है कि वर्तमान में राज्य सरकार मेरी ओर विशेष ध्यान दे रही है। अपने रक्षकों के अथक प्रयासों से मैं वहां से बाघों का स्रोत क्षेत्र बन चुका हूँ, जहां कभी उनका नामोनिशान भी नहीं था। मैं आज फल-फूल रहा हूँ, और मेरे साथ वे निःशब्द जीव भी आनंद से विचर रहे हैं, जिनकी धड़कनों में जीवन की उमंग फिर से जाग उठी है। मेरा अस्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, ताकि मैं भारत में बाघों के वितरण की पश्चिमी सीमा होने का गौरव सदैव बनाए रख सकूँ।

ऊँची उड़ान का राजा

बार हेडेड गूज़

– राज कुमार शिवानी, अतिरिक्त निदेशक
बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बार हेडेड गूज़ को स्थानीय भाषा में 'बिरवा' या 'भाटा' भी कहते हैं। यह अपने सफेद भूरे सिर पर काली पट्टियों की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है और इन्हीं काली पट्टियों के वजह से इसे यह बार हेडेड गूज़ का नाम मिला है। यह दुनिया का सबसे ऊँचाई पर उड़ने वाला पक्षी है, जो सुदूर मंगोलिया और सेंट्रल एशिया से हिमालय पर्वत श्रृंखला को पार करता हुआ प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में दक्षिण एशिया विशेषकर भारतवर्ष में प्रवास करने के लिए आता है। प्रवास की अवधि में यह आर्द्र भूमियों और झीलों के किनारे छोटी घास के मैदानों में सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में चरते हुये दिखाई पड़ते हैं।

राजस्थान के कई जिलों में बिखरी वाटरबॉडीज और तालाबों में भी इसके प्रवास के समय इसकी साइटिंग होती है। भरतपुर जिले के केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, कानोता बांध, चंदलाई, अभेड़ा कोटा, अजमेर में पुष्कर, आनासागर, जोधपुर की कुछ झीलों में भी इसकी साइटिंग की जाती है।

इतनी ऊँचाई पर उड़ने के लिए इस पक्षी ने अपने आप में अनेक अनुकूलताएं विकसित कर ली हैं। यह पक्षी कम ऑक्सीजन में भी उड़ान भर सकता है। इसके लिए इसने अपने हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने का रास्ता खोज लिया है और साथ ही अपनी हृदय की मांसपेशियों को इतना मजबूत बना लिया है कि कम ऑक्सीजन होते हुए भी यह लंबी दूरी तक लगातार उड़ान भरने के साथ-साथ रक्त संचारित करता रहता है, इसने अपने फेफड़ों को आश्चर्यजनक रूप से फुला लेने की क्षमता विकसित कर ली है। अपने औसत भार की तुलना में इसके पंखों का क्षेत्रफल अधिक होना, इसकी ऊँची उड़ान में सहायक होता है। प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य में कदम्ब नाम से उल्लेखित यह पक्षी भारतीय संस्कृति में सौंदर्य, शुचिता एवं अदम्य साहस का प्रतीक है। ■





राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय गौरव - रामसर साइट 'मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स'

जहां पहुंच मेहमान परिंदों को मिलता आसरा

बर्ड विलेज मेनार के जलाशयों पर है सिर्फ परिंदों का हक

– डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान का नाम लेते ही अधिकतर लोगों के मन में रेत से आच्छादित धूसर भूमि की छवि उभरती है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि राज्य का दक्षिणांचल-मेवाड़-वागड़ क्षेत्र- हरितिमा, जलप्रचुरता और जैव विविधता की अनमोल धरोहर समेटे हुए है। यह क्षेत्र प्राचीन अरावली की उपत्यकाओं, बलखाती नदियों, मानसून में झरते झरनों, निर्मल झीलों और सघन वनों के साथ, पशु-पक्षियों का भी स्वर्ग है। महान कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता, “अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा...” मानो इसी क्षेत्र पर सटीक बैठती है। सात समंदर पार से पक्षी हर वर्ष इसी क्षेत्र में शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं और बर्ड विलेज मेनार उनके लिए सबसे प्रिय ठिकानों में एक है।

परिंदों का स्वर्ग

उदयपुर से 50 किमी दूर स्थित मेनार गांव में धण्ड और ब्रह्म तालाब दो ऐसे अद्वितीय जलाशय हैं, जो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित हैं। ग्रामीणों द्वारा सदियों से इन तालाबों को परिंदों के लिए संरक्षित रखा गया है। यही कारण है कि

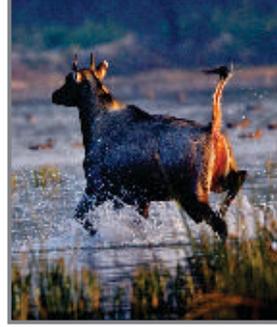
यहां हर मौसम में पक्षियों की चहचहाहट और जलक्रीड़ाएं सुनाई देती हैं।

35 वर्षों का इंतजार

वर्ष 2025 में मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। यह उपलब्धि 35 वर्षों बाद राजस्थान के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इससे पहले केवल केवलादेव (1981) और सांभर झील (1990) को ही यह मान्यता मिली थी। साथ ही, फलौदी का खीचन गांव भी अब रामसर साइट की सूची में शामिल हो चुका है।

संरचना और भौगोलिक विस्तार

यह वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 463.414 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें धण्ड तालाब (64 हेक्टेयर), ब्रह्म तालाब (53.1 हेक्टेयर) और खेरोदा तालाब (46.3 हेक्टेयर) शामिल हैं। इन जलाशयों के साथ मानसून में जलमग्न होने वाले कृषि क्षेत्र और झाड़ीदार भूमि भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं।



संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण

यहां अब तक 259 पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 110 जलपक्षी हैं। इनमें 67 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं।

गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां – लॉन्ग बिल्ड वल्चर, व्हाइट रम्पड वल्चर

संकटग्रस्त प्रजातियां – इंडियन स्कीमर, इजिप्शियन वल्चर, स्टेपी ईगल

अन्य संवेदनशील प्रजातियां – सारस क्रेन (यहां प्रजनन करता है), रिवर टर्न, व्हाइट नेड टीट, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, कॉमन पोचर्ड आदि

ग्रामीणों द्वारा संरक्षण – एक अनुकरणीय उदाहरण

मेनार के ग्रामीणों ने इन जलाशयों को परिंदों के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया है। यहां सिंचाई के लिए तालाबों से पानी नहीं लिया जाता। मत्स्याखेट और मछली पालन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। कमल या सिंघाड़े की खेती के लिए ठेका नहीं दिया जाता। तालाब सूखने पर, ग्रामीण टैंकर से पानी भरते हैं, ताकि मछलियां और पक्षी जीवित रह सकें। तालाब के पेटे में कृषि कार्य नहीं होता, चाहे पानी पूरी तरह सूख ही क्यों न जाए। यह न केवल राजस्थान, बल्कि देश के लिए भी पारिस्थितिकी और जनसहभागिता का एक उदाहरण है।

सर्दियों में परिंदों का कलरव

हर साल सर्दियों में यहां सैकड़ों पक्षी प्रजातियां हजारों की संख्या में आते हैं।

प्रवासी मेहमान – बार हेडेड गूज, ग्रे लेग गूज, डालमेशियन पेलिकन, रोजी पेलिकन, फ्लेमिंगो, कॉमन क्रेन, गॉडविट, शॉवलर, पिनटेल आदि

अन्य प्रमुख पक्षी – ब्लैक टेल्ड गॉडविट, ब्लैक नेक्ड स्टॉक, ओरिएंटल डार्टर, पेंटेड स्टॉक, सारस क्रेन, यूरोशियन कलर्यू, कलर्यू सैंडपाइपर

यह स्थान सालभर पक्षी प्रेमियों, पर्यटकों और वैज्ञानिकों की पसंदीदा साइट बना रहता है।

हिमालय से आया और यहीं का हो रहा

एक अनोखा पक्षी, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, जो कभी हिमालय से सर्दियों में आता था, अब यहीं स्थायी रूप से बस गया है। यह जलपक्षी तालाब के किनारे दलदली क्षेत्र में घोंसला बनाता है और जल में गोता लगाकर शिकार करता है। यह ब्रीडिंग भी यहीं कर रहा है, जो मेनार के अनुकूल पर्यावरण का प्रमाण है।

पादप और स्तनधारी विविधता

70 पादप प्रजातियां – जैसे ग्लोरियोसा सुपरबा, मोरिंगा कोंकानेन्सिस, प्लम्बागो जायलैनिका

12 स्तनधारी प्रजातियां – नीलगाय, सियार, जंगली बिल्ली, नेवला, पाम सिवेट, उड़न गिलहरी (ब्रह्म तालाब में), लंगूर, खरगोश आदि

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की धरोहर

मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स न केवल जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, बल्कि यह ग्रामीण सहभागिता, सामुदायिक संरक्षण, और पारिस्थितिकीय संतुलन का अनुपम उदाहरण भी है। यह स्थल भारत की प्राकृतिक धरोहरों में से एक है और इसके संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रत्येक प्रयास न केवल पक्षियों के लिए, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी आवश्यक है। ■

मछली 'वन की रानी' है



रणथंभौर की रानी, लेडी ऑफ द लेक और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बाघिन थी मछली (T-16)।

उसकी पहचान उसके चेहरे पर बने मछली जैसे निशान से हुई और यही नाम उसकी 'अमर पहचान' बन गया। वर्ष 1997 की बारिशों में जन्मी मछली बचपन से ही निडर और अलग थी। मात्र दो वर्ष की उम्र में उसने शिकार करना शुरू कर दिया और जल्द ही रणथंभौर के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्र पर कब्जा जमाकर जंगल की असली रानी बन गई।

मछली की शान यह थी कि उसने न सिर्फ नर बाघों से मुकाबला किया, बल्कि एक 14 फीट लंबे मगरमच्छ को भी परास्त किया। उसकी चाल में शाही गरिमा और आंखों में अदम्य साहस झलकता था। इसी वजह से उसे 'लेडी ऑफ द लेक' और 'क्रोकोडाइल किलर' जैसी उपाधियां मिलीं। पर्यटकों के सामने निडर होकर आने वाली यह बाघिन कैमरों की जान थी। यही कारण है कि उसे दुनिया की सबसे ज्यादा 'फोटो खींची गई बाघिन' कहा गया। उसके नाम पर डॉक्यूमेंट्री बनीं, रिसर्च पेपर्स लिखे गए और यहां तक कि भारत सरकार ने उसके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।

मछली ने मां, योद्धा और रानी, तीनों रूपों में अपनी ताकत दिखाई। उसकी संतानों को दूसरे रिजर्व में भेजा गया, जिससे वहां बाघों की संख्या बढ़ सकी। इस तरह उसने अपनी प्रजाति के संरक्षण में भी अमूल्य योगदान दिया। 18 अगस्त 2016 को जब 19 साल की उम्र में उसने अंतिम सांस ली, तो पूरा



जंगल मानो थम-सा गया। यह किसी बाघिन की असाधारण आयु थी, क्योंकि सामान्यतः जंगली बाघिन 10-15 साल तक ही जीवित रहती हैं।

विरासत

- रणथंभौर की असली रानी, बाघ संरक्षण की प्रतीक
- पर्यटन से भारत सरकार को करोड़ों की आय
- 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित
- डॉक्यूमेंट्री 'The World's Most Famous Tiger' को राष्ट्रीय पुरस्कार
- मगरमच्छ का शिकार कर जंगल की दंतकथा बनी
- पर्यटन और फोटोग्राफी की शान

ऐरोहेड... उसकी 'असली' निशानी है



मछली सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, वह रणथंभौर की आत्मा थी। उसकी दहाड़ अब भी झीलों की लहरों में गूंजती है। रानियां मरती नहीं, वे इतिहास बन जाती हैं।

मछली की शाही उत्तराधिकारी-ऐरोहेड

रणथंभौर की झीलों पर राज करने वाली और मछली की शाही विरासत को आगे बढ़ाने वाली बाघिन थी ऐरोहेड (T-84)। वर्ष 2014 में जन्मी बाघिन अपनी मां कृष्णा व दादी मछली की तरह ही खूबसूरती और ताकत का संगम थी। उसके सिर पर बने तीर जैसे निशान ने उसे अनूठी पहचान दी और उसका नाम पड़ा 'ऐरोहेड'।

शुरुआत से ही उसने झीलों के किनारे अपनी मौजूदगी से सबको मोहित किया। मगर उसकी असली शौर्य गाथा तब गूंजी, जब उसका मगरमच्छ का

शिकार करते हुए वीडियो वायरल हुआ। इस कारनामे ने उसे 'क्रोकोडाइल हंटिंग टाइग्रेस' की उपाधि दिलाई। धीरे-धीरे उसने रणथंभौर के जोन 2, 3, 4 और 5 पर कब्जा कर लिया। उसकी शाही चाल और आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे भारत की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली बाघिनों के ग्रुप में शामिल कर दिया।

अपनी दादी मछली की तरह ऐरोहेड भी शानदार मां साबित हुई। उसने शावकों को जन्म दिया और हर खतरे से उनकी रक्षा की। उसका मातृत्व उसके शिकार जितना ही साहसी था, लेकिन 2025 की शुरुआत में उसकी जिंदगी अंधकारमय हो गई। एक ट्यूमर ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया। 19 जून 2025 को उसने अंतिम बार शाही अंदाज में जंगल की पगडंडियों पर कदम रखा मानो कोई रानी अपने महल से अंतिम बार निकल रही हो। कुछ ही समय पहले उसके शावकों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था, मानो उसकी गाथा का चक्र पूरा हो रहा हो।

उसकी अंतिम यात्रा का वीडियो इंटरनेट पर छा गया। थकी हुई मगर गरिमामयी चाल को देखकर लोग भावुक हो उठे। कहा गया कि यह सिर्फ ऐरोहेड का अंत नहीं, बल्कि रणथंभौर की एक ताकतवर गूंज का अंत है।

ऐरोहेड सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, वह रणथंभौर की धड़कन थी। आज और आगे जंगल के किस्सों में उसका भी नाम आदर और गर्व से लिया जाएगा। ■

वन्यजीव अभयारण्य एवं इको टूरिज्म

छाया : राममोहन मीणा, एसीएफ

हजारों देशी-विदेशी पर्यटक जैव विविधता निहारने आते हैं प्रतिवर्ष

राजस्थान में वन का क्षेत्रफल देश में कई राज्यों की तुलना में कम होने के बावजूद वन्यजीवों की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 से लागू है, जिसके तहत बिना अनुमति के शिकार को निषिद्ध घोषित किया है।

– हरिओम सिंह गुर्जर, संयुक्त निदेशक

राज्य में वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास को जानने के लिए भू-संरचना के अनुसार प्रदेश को चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जिनमें मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देशभर में अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इनमें वानस्पतिक विशिष्टताओं, जैव विविधताओं को देखने दुनियाभर से पर्यटक आते रहते हैं। प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य अपनी जैव विविधताओं, वनस्पति एवं स्थानीय लोक सांस्कृतिक विशेषताओं के चलते इको टूरिज्म के लिए पसंदीदा स्थल बनते जा रहे हैं।

राज्य के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दुनियाभर में पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार कोटा से लेकर धौलपुर जिले तक फैले चम्बल राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य को घड़ियालों एवं मगरमच्छों की शरण स्थली कहा जाता है। राष्ट्रीय मरुउद्यान दुनियाभर में लुप्तप्राय गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश में आने वाले हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों को यहां के वन्यजीव अभयारण्यों में जैव विविधता, ऐतिहासिक किले-महल, लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहां के मेलों, उत्सवों में प्रदेश की बहुरंगी संस्कृति के दर्शन होते हैं तो अभयारण्यों की जैव विविधता, वानस्पतिक विशेषताओं और अभयारण्यों के समीप लोक जीवन को देखने हजारों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं।

राजस्थान इको टूरिज्म नीति प्राकृतिक, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसके तहत सामुदायिक भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, संस्कृति, स्वदेशी ज्ञान और प्रथाओं, पर्यावरण शिक्षा और नैतिकता के साथ-साथ आर्थिक लाभ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नीति के अन्तर्गत मेजबान समुदाय के संवर्धन और पर्यटकों की संतुष्टि के लिए प्रयास किया जाता है। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए अभयारण्य क्षेत्रों में ट्रेकिंग मार्ग तैयार करना, जैव विविधता को निहारने के लिए व्यू पाइंट तैयार करना, आगन्तुक देशी-विदेशी मेहमानों के लिए अभयारण्यों में आवागमन के लिए पर्यावरणीय अनुकूल वाहनों की व्यवस्था की जाती है। समीप के क्षेत्रों में भोजन-आवास आदि के लिए अनुकूलता प्रदान कर वन क्षेत्रों में रहे स्थानीय लोगों की भलाई के लिए भी कार्य किया जाता है।



**केवलादेव घना
राष्ट्रीय पक्षी उद्यान**



**मुकुन्दरा हिल्स
राष्ट्रीय उद्यान**



राष्ट्रीय मरुउद्यान

स्थान : भरतपुर

विशेषताएँ

- राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान
- विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल (UNESCO, 1985)
- पक्षियों का स्वर्ग और पक्षियों की एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली
- रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध नम भूमि क्षेत्र

वनस्पति

1. कदम्ब के पेड़
2. अकेशिया के घने वन

जीव-जंतु

- मुख्य आकर्षण – साइबेरियाई क्रेन (दुर्लभ प्रवासी पक्षी)
- अन्य – गीज, सफेद मोर, पोचार्ड, लेपबिंग, बेगटेल, रोजी पेलीकन, अजगर

जलस्रोत

गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम से बना अजान बाँध, जिसकी छिछली झीलों से उद्यान में जल आता है।

स्थान : कोटा

विशेषताएँ

- राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान
- दर्जा अभयारण्य व जवाहर सागर अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया
- मुकुन्दरा पर्वतमालाओं में आदिमानव शैलाश्रय व शैलचित्र पाए जाते हैं

वनस्पति

- पर्वतीय वनों का क्षेत्र
- विविध झाड़ीदार और पर्णपाती पेड़-पौधे

जीव-जंतु

- प्रमुख – सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, जंगली सूअर
- विशेष – गागरोनी व हीरामन तोते

जलस्रोत

कोटा-झालावाड़ मार्ग पर स्थित क्षेत्र, जिसमें झीलें और प्राकृतिक स्रोत शामिल हैं।

स्थान : जैसलमेर व बाड़मेर

विशेषताएँ

- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान (3162 वर्ग किमी)
- थार मरुस्थल की अनूठी जैव विविधता का संरक्षण

वनस्पति

- मरुस्थलीय झाड़ियाँ
- सूखा सहनशील पौधे

जीव-जंतु

- मुख्य आकर्षण – गोडावण (राज्य पक्षी, पूर्ण संरक्षण प्राप्त)
- अन्य – गिद्ध, पीवणा कोबरा, रसल्स वाइपर, स्केल्ड वाइपर आदि

जलस्रोत

वर्षा आधारित प्राकृतिक जलधाराएँ व रेतीले क्षेत्र के छोटे स्रोत



रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान

स्थान : सवाई माधोपुर

विशेषताएँ

- राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान
- “टाइगर का घर” के नाम से प्रसिद्ध
- त्रिनेत्र गणेश मंदिर व जोगी महल के लिए प्रसिद्ध

वनस्पति

- मिश्रित पर्णपाती वन
- प्रमुख वृक्ष – धोंक

जीव-जंतु

- मुख्य आकर्षण – बाघ
- अन्य – सांभर व चीतल

जलस्रोत

पदम तालाब, राजबाग, मलिक तालाब, मानसरोवर और गिलाई सागर

सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान

स्थान : अलवर

विशेषताएँ

- दर्शनीय स्थल – पाण्डुपोल हनुमान मंदिर, सरिस्का पैलेस, भर्तृहरि जी, नीलकंठ महादेव मंदिर, कांकनवाड़ी दुर्ग

वनस्पति

- प्रमुख वृक्ष – धोंक
- अन्य – सालर, बेर, बाँस, कैर, अडुस्टा, झर बेर

जीव-जंतु

- प्रमुख – बाघ, तेंदुआ, कैरकल, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा
- अन्य – जंगली बिल्ली, बिज्जू, सियार, चौसिंगा मृग, जंगली सूअर, खरगोश, लंगूर, पक्षी प्रजातियाँ व सरिसृप

जलस्रोत

प्राकृतिक पहाड़ी नाले व झीलें, जो बाघों और अन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी हैं





राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य

स्थान : कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ

वनस्पति

- प्रमुख वृक्ष - पलाश, खैर, बेर
- चुरेल, बबूल व काँटेदार झाड़ियाँ; नदी किनारे घास

जीव-जंतु

- वन्यजीव - घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, दलदली मगरमच्छ, कछुओं की 8 प्रजातियाँ, मछलियों की 30 प्रजातियाँ, ऊदबिलाव, नीलगाय, जंगली सूअर, खरगोश, लोमड़ी, लकड़बग्घा, सुनहरा सियार, भारतीय भेड़िया
- पक्षी - भारतीय स्कीमर, सारस क्रेन, गीज, फ्लेमिंगो सहित 316 से अधिक प्रजातियाँ

जलस्रोत

चंबल नदी



ताल छापर अभयारण्य

स्थान : छापर, चूरू

विशेषताएँ

- काले हिरणों (कृष्ण मृग) के लिए प्रसिद्ध
- प्रवासी पक्षी कुरजां का प्रजनन स्थल

वनस्पति

- वर्षा के मौसम में उगने वाली मोचिया साइप्रस रोटन्डस घास

जीव-जंतु

- काले हिरण
- विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी

जलस्रोत

प्राचीन भैंसोलाव और डूंगोलाव तलैया



सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य

स्थान: प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़

विशेषताएँ

- अरावली, विन्ध्याचल और मालवा पर्वतमालाओं का संगम, ऊँचे सागवान वनों की उत्तर-पश्चिमी सीमा
- प्रमुख जल स्रोत - जाखम नदी

वनस्पति

- वृक्ष, घास, लताओं और झाड़ियों की बेशुमार प्रजातियाँ
- दुर्लभ औषधि वृक्ष और जड़ी-बूटियाँ

जीव-जंतु

- स्तनधारी और सरीसृप - उड़न गिलहरी, चौसिंघा हिरण सहित अन्य प्रजातियाँ; उभयचर - लगभग 40 प्रजातियाँ
- पक्षी - 300+ प्रजातियाँ, कई प्रजनन के लिए अन्य हिस्सों से यहाँ आते हैं

जलस्रोत

जाखम नदी



**माउंट आबू वन्यजीव
अभयारण्य**

स्थान: माउंट आबू, सिरोही

विशेषताएँ

- अरावली पर्वतमाला में स्थित, माउंट आबू का प्रमुख पर्यटक स्थल
- जैव विविधता में विशेष पादप – डिकिल्पटेरा आबून्सिस, केवल माउंट आबू पर पाया जाता है
- पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए वन्यजीव और वनस्पति अवलोकन का अवसर

वनस्पति

- 112+ प्रजातियाँ, जिसमें विशिष्ट पर्वतीय पौधे शामिल
- क्षेत्रीय शुष्क-पर्णपाती वन और झाड़ियाँ

जीव-जंतु

- स्तनधारी – जंगली मुर्गा, तेंदुआ, स्लोथबियर, वाइल्ड बोर, सांभर, चिंकारा, लंगूर
- पक्षी – लगभग 150 प्रजातियाँ

जलस्रोत

प्राकृतिक जल स्रोत और छोटे जलाशय



**सज्जनगढ़ वन्यजीव
अभयारण्य**

स्थान: उदयपुर

विशेषताएँ

- अरावली के बांसदरा पहाड़ी की चोटी पर स्थित
- राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य
- लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, जैसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध

वनस्पति

- पहाड़ी क्षेत्र की शुष्क-पर्णपाती वनस्पति
- स्थानीय झाड़ियाँ और पर्वतीय पौधे

जीव-जंतु

- स्तनधारी और सरीसृप – स्थानीय लुप्तप्राय प्रजातियाँ
- पक्षी – सरकोगिप्स कैल्वस, जिप्स इंडिकस, जिप्स बेंगालेंसिस, श्वेत गर्दन वाली टिस् पारस नुचौलिस सहित 129 प्रजातियाँ

जलस्रोत

क्षेत्रीय छोटे जलस्रोत और पहाड़ी धाराएँ



**रामगढ़ विषधारी
अभयारण्य**

स्थान: बूंदी

विशेषताएँ

- देश का 52वाँ एवं राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व
- रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के निकट होने के कारण बाघों के प्राकृतिक विचरण के लिए उपयुक्त
- अभयारण्य के माध्यम से चंबल की सहायक नदी मेज गुजरती है

वनस्पति

- मिश्रित वन और झाड़ीदार क्षेत्र
- स्थानीय पर्णपाती पेड़ और घास के मैदान

जीव-जंतु

- वन्यजीव – बाघ, बघेरा, रीछ, गीदड़, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सूअर, नेवला, खरगोश, भेड़िया
- पक्षी – विभिन्न रंग-बिरंगी प्रजातियाँ

जलस्रोत

मेज नदी – चंबल की सहायक नदी, जो अभयारण्य में बहती है। ■

हर बारिश के बाद होती है पुश्तैनी घरौंदों की मरम्मत



जवाई बांध क्षेत्र की चट्टानों में अबाबील (Indian Cliff Swallow) पक्षियों द्वारा बनाए गए पुश्तैनी घोंसलों की हर वर्ष बारिश के बाद मरम्मत की जाती है। ये पक्षी नर-मादा मिलकर ताजा कीचड़ और अपनी लार से घोंसलों की मरम्मत करते हैं। ये घोंसले मधुमक्खियों के छत्तों जैसे समूहों में होते हैं और चट्टानों पर उल्टे चिपके होते हैं, जिससे ये परभक्षियों से सुरक्षित रहते हैं। मरम्मत पूरी होने के बाद मादा अंडे देती है और दोनों मिलकर चूजों का पालन करते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और प्रकृति में इनके योगदान का एक सुंदर उदाहरण है। अगस्त के अंत तक एक नई पीढ़ी जन्म लेती है, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाती है। ■

आलेख व छाया : लक्ष्मण पारंगी, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर

चंबल में कछुओं की घर वापसी

3,267 नन्हे जीवन संग लौटी नई उम्मीद

राजस्थान वन विभाग ने TSA फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, धौलपुर में दो गंभीर रूप से संकटग्रस्त कछुओं रेडक्राउन रूफड टर्टल (बाटागुर कछुगा) और श्री-स्ट्राइप्ड रूफड टर्टल (बाटागुर ढोनकोगा) के संरक्षण की पहल शुरू की।

डॉ. आशीष व्यास के नेतृत्व में और स्थानीय अधिकारियों, TSA कर्मचारियों व ग्रामीणों की मदद से 35 किमी नदी खंड में नेस्ट पेट्रोलिंग की गई। 160 घोंसलों से 3,470 अंडों को सुरक्षित अस्थायी हैचरी में स्थानांतरित किया गया, जिसमें से 3,267 कछुए (95% सफलतापूर्वक) जन्मे और मई माह में नदी में छोड़े गए।

यह परियोजना संकटग्रस्त प्रजातियों के दीर्घकालिक पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रयास को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 में प्रदर्शित किया गया और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा सराहा गया। ■





लूंग में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व

कूड प्रोटीन : 14-18 %

फाइबर : 15-20 %

खनिज लवण : 8 %

कच्ची सांगरी में पाए जाने वाले तत्व

प्रोटीन : 8%

कार्बोहाइड्रेट : 58%

रेशा : 28%

वसा : 2%

कैल्शियम : 0.4%

लौह तत्व : 0.2%

खेजड़ी रूत आयां पांघरसी

– हिमांशु सिंह, जनसंपर्क अधिकारी

छांग्यो लूंग टाटड्यां ताई, नागी बूची कर दी,
लाज लूंट ली आं निमल्यां री, लूठां जोरांमरदी,

भर्ये सियाळे डांफर पाळे, साव उधाड़ी ठरसी।
खेजड़ी, रूत आयां पांघरसी।

बै तपता बैसाख जेठ रा, महीनां मिनख भुलाया,
सावणियै रा सपनां देख्या, ई री ठंडी छायां,

पण कुदरत दातार, बापड़ी, फेर फूलसी फळसी।
खेजड़ी रूत आयां पांघरसी।

राजस्थान के मूर्धन्य कवि श्री कन्हैयालाल सेठिया की राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर लिखी गई यह पंक्तियां खेजड़ी और मनुष्य के आपसी संबंधों व अंतर्निभरता को बताने के लिए पर्याप्त हैं। 'खेजड़ी रूत आया पांघरसी' का तात्पर्य है कि खेजड़ी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल मौसम आने पर पुनः फलती-फूलती है। रेगिस्तान के लोगों की भांति ही खेजड़ी के वृक्ष की भी जीवटता अनोखी है।

थार के रेगिस्तान में यह जीवनयापन के लिए 'हमजोली' के रूप में सदियों से यहां के निवासियों के साथ है। इसकी छाया में जहां पशु-पक्षी और मनुष्य भी अपना आवास बनाते हैं, वहीं इसकी लूंग (पत्तियां) बकरियां, भेड़, गाय, भैंस, ऊंट, इत्यादि के लिए पौष्टिक चारे के काम आती हैं। वहीं इसकी सूखी पत्तियां फसलों के लिए खाद का कार्य करती है।

केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान, बीकानेर द्वारा खेजड़ी की कलम विधि से कांटे रहित उन्नत किस्म 'थार शोभा' विकसित की गई है। यहां कलिकायन किए पौधों का उचित रखरखाव करने से तीसरे वर्ष में ही सांगरी उत्पादन शुरू हो जाता है। इस किस्म की कम ऊंचाई के कारण कटाई-छंटाई व सांगरी की तुड़ाई भी आसानी से हो जाती है। कच्ची सांगरी का बाजार भाव लगभग 300 रुपए प्रति किलो और सूखी फली को 1,400 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचा जा सकता है। प्रति पेड़ 4.2 से 5.3 किग्रा सांगरी प्राप्त होती है, वहीं 8.8 से 9.9 किग्रा तक लूंग का चारा भी उपलब्ध होता है।

कलमी खेजड़ी आधारित कृषि वानिकी मॉडल

काजरी में कृषि वैज्ञानिक डॉ. धीरज सिंह बताते हैं कि काजरी द्वारा कलमी खेजड़ी के रूप में एक कृषि वानिकी मॉडल का विकास और मानकीकरण किया गया है, जिसमें कलम की गई खेजड़ी को शुष्क क्षेत्र की फसलों यथा मूंग और बाजरा के साथ उचित दूरी पर लगाया जाता है। काजरी द्वारा विकसित इस मॉडल से किसान एक तरफ जहां रासायनिक खाद के बेतहाशा इस्तेमाल से बच रहे हैं, वहीं आर्थिक रूप से भी यह काफी फायदेमंद साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चलाए जा रहे 'हरयालो राजस्थान' अभियान के तहत भी प्रदेश में खेजड़ी के लाखों पौधे लगाए गए हैं, जो जल्द ही वृक्ष बनकर रेगिस्तान में सिर उठाकर प्रकृति संरक्षण की इस मानवीय पहल की कहानी कहेंगे। ■

हरित धरा संग डिजिटल धारा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) लाए नया उजियारा

– डॉ. आशीष खण्डेलवाल, उप निदेशक

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। राजस्थान अपनी समृद्ध जैव-विविधता, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसे विश्व प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार के वन विभाग ने ई-गवर्नेंस और डिजिटल पहलों के माध्यम से इस दिशा में अपूर्व कार्य किए हैं, जिससे वन प्रबंधन और संरक्षण में नया युग शुरू हुआ है। पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में आईटी और एआई का उपयोग कई तरीके से हो सकता है।

वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार रोकथाम

वन विभाग ड्रोन और एआई-संचालित कैमरों का उपयोग शुरू कर वन्यजीवों की गतिविधियों पर सतत नजर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, देश के कई टाइगर रिजर्व में ट्रेलगार्ड एआई कैमरा ट्रैप्स का उपयोग किया जा रहा है, जो वन्यजीवों की तस्वीरें खींचकर प्रजातियों की पहचान करते हैं और संभावित अवैध शिकार की गतिविधियों के बारे में वन रेंजर्स को तुरंत सूचित करते हैं। यह तकनीक विशेष रूप से बाघों और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों, जैसे तेंदुए और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा में प्रभावी है।

वनाग्नि प्रबंधन

शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वन में लगने वाली आग एक बड़ी चुनौती है। एआई-सक्षम सिस्टम और थर्मल सेंसर का उपयोग करके वन विभाग आग

के खतरों का पूर्वानुमान लगाता है। ये सिस्टम संवेदनशील क्षेत्रों में असामान्य गतिविधियों का पता लगाकर वन अधिकारियों को तत्काल सूचनाएं भेजते हैं, जिससे समय पर कार्रवाई संभव हो पाती है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग वन में नुकसान पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है।

पर्यावरणीय डेटा विश्लेषण

एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से वन विभाग उपग्रह चित्रों (जैसे इसरो के भुवन प्लेटफॉर्म, कार्टोसैट और रिसोर्ससैट) और ड्रोन डेटा का विश्लेषण करते हैं। यह वन कवर में परिवर्तन, अवैध कटाई और अतिक्रमण की निगरानी में मदद करता है। उच्च-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अतिक्रमण पहचान के लिए डिजिटल मैप भी तैयार किए जा रहे हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन

मानव-वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या है। इससे बचने के लिए अभयारण्यों में एआई-संचालित कैमरा ट्रैप्स और जियोफेंसिंग तकनीक का उपयोग करके वन्यजीवों की गतिविधियों को ट्रैक किया जाता है। ये सिस्टम स्थानीय समुदायों को समय पर चेतावनी देकर पशुधन और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

पर्यावरणीय डीएनए (ईडीएनए) विश्लेषण

ईडीएनए तकनीक का उपयोग करके जल और मिट्टी के नमूनों से दुर्लभ प्रजातियों, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, की उपस्थिति का पता लगाया जा रहा है। यह तकनीक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है।



राजस्थान वन विभाग की ई-गवर्नेंस पहल

राजस्थान वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, अरण्यक aaranyak.forest.rajasthan.gov.in एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वेबसाइट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजीजन सपोर्ट सिस्टम (FMDSS 2.0) का हिस्सा है, जो नागरिकों, पर्यटकों और वन अधिकारियों के लिए एक एकीकृत और उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच प्रदान करती है। अरण्यक वेबसाइट को उपयोगकर्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका इंटरफेस सरल और सहज है, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं, नागरिकों, पर्यटकों और वन अधिकारियों के लिए उपयुक्त है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं -

लॉगिन पोर्टल और सिंगल साइन-ऑन (SSO) एकीकरण : अरण्यक वेबसाइट राजस्थान सरकार के सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल (<https://sso-rajasthan-gov-in>) के साथ एकीकृत है। उपयोगकर्ता अपने SSO ID का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं, जिससे कई खातों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह सुविधा नागरिकों और अधिकारियों को वैयक्तिकृत सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती है।

ऑनलाइन सफारी और परमिट बुकिंग : वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क (कोटा), बर्ड पार्क (जयपुर और उदयपुर) और चंबल पालीघाट बोट सफारी जैसे विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन सफारी और परमिट बुक कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा गंतव्य और समय स्लॉट का चयन कर सकते हैं और वास्तविक समय में उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नर्सरी पौधों की खरीद : अरण्यक वेबसाइट के नर्सरी प्लॉट्स अनुभाग के माध्यम से उपयोगकर्ता वन विभाग की पौधशालाओं से विभिन्न प्रजातियों के पौधे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यह सुविधा 'ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया' कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राजस्थान में करोड़ों पौधे लगाने

का है। उपयोगकर्ता अपनी एसएसओ आईडी के साथ नर्सरी और पौधों का चयन कर सकते हैं और फिर संबंधित नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा वनरोपण, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने और जैव-विविधता बढ़ाने में योगदान देती है।

फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजीजन सपोर्ट सिस्टम (FMDSS) : अरण्यक FMDSS 2.0 का एक अभिन्न अंग है, जो वन विभाग की सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं को एक एकीकृत वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित करता है। यह बजट नियोजन, निगरानी और वन प्रबंधन के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह प्रणाली मुख्यालय, मंडलीय कार्यालयों, रेंज कार्यालयों और वन स्थलों के बीच वास्तविक समय में जानकारी और सेवाओं के आदान-प्रदान को आसान बनाती है। प्रक्रियाओं और फॉर्मों के मानकीकरण से प्रशासनिक कार्यों में सरलता और पारदर्शिता बढ़ी है।

जैव-विविधता और संरक्षण संसाधन : अरण्यक वेबसाइट राजस्थान के जंगलों, वन्यजीवों और संरक्षण प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इसके संसाधन अनुभाग में जैव-विविधता रिपोर्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और थार रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र पर अध्ययन और जल संरक्षण व टिकाऊ जीवन शैली के लिए गाइड शामिल हैं। यह अनुभाग शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और पर्यावरण प्रेमियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

जियोस्पेशियल उपकरण और जीआईएस मैपिंग : वेबसाइट पर जियोस्पेशियल टूल भी उपलब्ध हैं, जो वन कवर, संरक्षित क्षेत्रों और जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स की दृश्य जानकारी प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता वन घनत्व, रणथंभौर और सरिस्का जैसे अभयारण्यों की सीमाएं और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के इंटैक्टिव नक्शे देख सकते हैं। यह टूल शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और इको-टूरिस्टों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

शैक्षिक और अनुसंधान समर्थन : अरण्यक वन्यजीव फोटोग्राफी, अनुसंधान और इको-टूरिज्म के लिए परमिट प्रदान करता है, जो शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए उपयोगी है।

अमृता देवी और पशु बचाव : वेबसाइट अमृता देवी बिश्रोई संरक्षण पहल और पशु बचाव गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करती है।

डिजिटल वन सीमाओं में गुणवत्ता सुधार : स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर की सहायता से वन सीमाओं को रेवेन्यू स्केल पर डिजिटलाइज करने का कार्य प्रगति पर है। 7 हजार वन खंडों में से लगभग 3 हजार, 27 वन्यजीव क्षेत्रों में से 5 और 36 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों में से 20 से अधिक के लिए प्रारंभिक डिजिटल डेटा तैयार किया जा चुका है।

डिजिटल वन सीमाओं का उपयोग : डिजिटल वन सीमाओं का उपयोग वन आग प्रबंधन, एसेट प्लानिंग, कार्य आयोजना मैपिंग और वन्यजीव कॉरिडोर की योजना बनाने में किया जा रहा है। जोधपुर वन मंडल में उच्च-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अतिक्रमण पहचान के लिए डिजिटल मैप तैयार किए जा रहे हैं। सिल्वा रिसर्च विंग के माध्यम से 1,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले दो वन खंडों में जिओस्पेशियल तकनीक का उपयोग कर डिजिटल डेटा एकीकरण और विश्लेषण का कार्य शुरू किया गया है। ■

राजस्थान के ओरण हमारी धरोहर

- जितेन्द्र राय गोयल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय



‘ओरण भूमि’ से आशय

‘ओरण’ या ‘देवबानी’ जंगलों का एक सामान्य संरक्षित क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र प्रत्येक गांव द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किसी देवी या देवता के नाम पर संरक्षित किया जाता है। एक ओरण का क्षेत्रफल कुछ वर्ग मीटर से लेकर कई सौ हेक्टेयर तक हो सकता है। जैसलमेर जिले में भादरिया ओरण 17,804.13 हेक्टेयर में विस्तृत है। जो देश का सबसे बड़ा ओरण है। एक अनुमान के अनुसार, राजस्थान राज्य में ओरण का कुल क्षेत्रफल 6,00,000 हेक्टेयर से अधिक है, जिसमें लगभग 25,000 ओरण शामिल हैं।

ओरण चारा, ईंधन, लकड़ी, वनोपज, जड़ और जड़ी-बूटियों जैसी प्राकृतिक संपदा का स्रोत रहे हैं। इन्हें उस समुदाय के लिए समृद्धि का प्रतीक माना जाता था जिसके पास ये होते थे। इसके अलावा, ओरणों ने राजस्थान में पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पशुपालक समुदायों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हमारे राज्य में पवित्र कुंज न केवल सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व रखते हैं, बल्कि साथ ही वे यहां के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं।

वस्तुतः जंगल, चारागाह एवं जल स्रोत, जिन्हें प्राचीन काल से ‘ओरण’ के रूप में भी पहचाना जाता रहा है, हमारे जीवन का आधार हैं। इनसे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इसी पवित्र विरासत में अंसख्य वनस्पतियां, पेड़-पौधे, वन्य जीव-जन्तु एवं प्रवासी पक्षियों का भी विचरण होता है और यही इनका प्रवास क्षेत्र भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण हमारे पूर्वजों द्वारा अपने लोक देवी-देवताओं के नाम पर अपने-अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक जंगलों को संरक्षित करने का संकल्प लेकर इनकी सुरक्षा व रख-रखाव हेतु कठोर नियम भी बनाए गए, जिनसे वे दीर्घकाल तक संरक्षित-सुरक्षित एवं उपयोगी रह सके।

यह उल्लेख करना भी प्रांसंगिक होगा कि समुदाय के लोगों के अन्दर अपने देवी-देवताओं के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, जिससे वशीभूत होकर वे ओरणों की रक्षा एवं संवर्धन करने को अपना दायित्व, अपना धर्म समझते रहे हैं, यही कारण रहा है कि लम्बे समय से ओरण सुरक्षित पलते-बढ़ते रहे हैं।

प्रकृति का यह सामान्य नियम है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सोच एवं मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। जिस भावना से लम्बे समय तक हमारे पूर्वजों ने

ओरणों की रक्षा की, उन्हें सहेजकर रखा, लेकिन वर्तमान में चिंतनीय है कि ओरणों, देवकुंजों के प्रति नई पीढ़ी में कोई उत्साह प्रतीत नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर हम अपने भविष्य में उठने वाले प्राकृतिक बवन्डरों को महसूस करने के प्रति उदासीन हो गए हैं। जिन प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा अपने प्राण देकर हमारे पूर्वजों द्वारा की गई थी, अब उनके प्रति असामान्य रूप से कमी देखी जा रही है। वर्तमान में हम अपने दायित्व विस्मृत करते जा रहे हैं। अगर हमारी बहुमूल्य विरासत ये ओरण नष्ट हो गए, तो प्रदेश एवं राष्ट्र के समक्ष प्राकृतिक असंतुलन का संकट सामने होगा। इसके परिणाम समस्त मनुष्य प्रजाति के लिए भयावह ही होंगे। इन्हीं सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जुलाई 2018 में आदेश पारित करते हुए राज्य में विद्यमान ओरणों की पहचान कर उनके उचित रूप से संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान के विभिन्न प्राकृतिक समूहों यथा ओरण, देववन, रुद्र व अन्य नामों से भी जाने पहचाने जाने वाले पवित्र कुंजों को मानित वन (Deemed forest) घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन स्थलों का वर्गीकरण उनके आकार या क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, बल्कि उनके उद्देश्य, और स्थानीय समुदाय के लिए उनकी सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक महत्ता के आधार पर किया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः 18 दिसम्बर, 2024 को ओरण के महत्वों एवं विशेषताओं को रेखांकित करते हुए इन्हें सम्पूर्ण राजस्थान में औपचारिक एवं कानूनी मान्यता प्रदान कर संरक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही अनाधिकृत अतिक्रमण एवं भूमि उपयोग परिवर्तन रोकने की

आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय समुदाय के सहयोग से सांस्कृतिक एवं पारम्परिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उचित मामलों में वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 36 सी के अन्तर्गत सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की है। साथ ही निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय समिति के गठन के निर्देश दिये हैं। यहां उल्लेखनीय है कि इस हेतु गठित राज्य ओरण समिति द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के जिला प्रशासन की सहायता से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए ओरण अथवा पवित्र कुंजों के पहचान की प्रक्रिया को गति मिल रही है। ओरणों को संरक्षित करने की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में समाज की सक्रिय भागीदारी को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रशासन भी सतत प्रयत्नशील है।

यह हमारे लिए संतोष का विषय है कि देव कुंजों को बचाने के लिये समाज के जागरूक वर्ग की सक्रिय भागीदारी भी मिल रही है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन (NGO) इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं एवं जन चेतना को जाग्रत करने एवं ओरणों के महत्व को जन-जन तक प्रसारित करने में सहयोगी के रूप में कार्यशील है। आशा है कि राजस्थान राज्य के सभी पवित्र कुंजों (ओरणों) के संरक्षण एवं जन जीवन में इनके बहुआयामी उपयोग की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को वांछित सफलता मिलेगी। ■





विधानसभा में युवा संसद का आयोजन

राष्ट्रहित का मुद्दा आया तो पक्ष-विपक्ष एक हुए

– डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा, उप-निदेशक



पीओके वापस लेने के प्रस्ताव के पक्ष में शत-प्रतिशत मत कश्मीरी छात्रा हदीका ने प्रस्तुत किया था प्रस्ताव

राष्ट्रहित की बात आई तो पक्ष-विपक्ष एकजुट हो गए। भारत के 10 राज्यों और 03 केन्द्र शासित प्रदेशों से आये युवाओं ने राज्य विधानसभा में आयोजित चौथे युवा संसद समारोह में भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों और पीओके के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और बताया कि आज भारत का युवा इस सम्बन्ध में क्या सोचता है? विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा विधान सभा में किए गए नवाचार के रूप में चौथी बार छात्र संसद का आयोजन अगस्त माह के पहले सप्ताह में किया गया।

युवा संसद में राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरात सहित तीन केन्द्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ व नई दिल्ली के 55 विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के चयनित 168 युवा छात्र-छात्राओं ने आतंकवाद और पाक के कब्जे वाले कश्मीर को खाली करवाने के प्रयासों पर संवाद किया। विधान सभा सदन में 56 युवाओं ने तर्कों और तथ्यों के साथ निर्धारित समय में अपनी बात रखकर संयमित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत किया।

तर्कों और तथ्यों के साथ संवाद

विधान सभा में युवा संसद का आयोजन राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में हुआ। राजस्थान विधान सभा सदन में 168 युवाओं ने देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर तर्कों और तथ्यों के साथ संवाद किया। खास बात यह रही कि उन्होंने पक्ष-विपक्ष में बैठकर भी राष्ट्र के मुद्दे पर एकजुटता दिखाई।

समझायी लोकतंत्र की संस्कृति

युवा संसद का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ करते हुए विधान सभा

अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने युवाओं को संसद की गरिमा, मर्यादा, नियम और परम्पराओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गौरवशाली भारत का लोकतंत्र और संविधान सुदृढ़ है। राष्ट्र हित में पक्ष और प्रतिपक्ष को एकजुट होना आवश्यक है। देश है तो हम हैं और यदि देश नहीं रहेगा, तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। देश के विभिन्न भागों से युवा संसद के लिए चयनित होकर आए छात्र-छात्राओं को श्री देवनानी ने लोकतंत्र की संस्कृति समझायी। उन्होंने कहा कि सदन में आते ही पहले प्रतिपक्ष की ओर मुखातिब होकर नमस्कार करना चाहिए, फिर पक्ष के सदस्यों का अभिवादन स्वीकार करना चाहिए। यह वह सदन है जहां लोकतंत्र के मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है, जन भावनाएं नीतियों में रूपान्तरित होती हैं और यहीं से जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

सदन जनप्रतिनिधि की नेतृत्व क्षमता का परीक्षा केन्द्र

इस सदन में जनप्रतिनिधि की लोकतांत्रिक चेतना, विचारशीलता और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होती है। तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहना, दूसरों की बात धैर्य से सुनने के साथ सहमति और असहमति के आधार पर सन्तुलन बनाना ही लोकतंत्र की संस्कृति है। युवा संसद युवाओं को सिर्फ आलोचक ही नहीं, भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन सकें।

लोकतंत्र के संस्कारों की जीवन्त शिक्षा का माध्यम

राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के सचिव श्री संदीप शर्मा ने कहा कि युवा संसद बोलने, विरोध दर्शाने या समर्थन का ही अभ्यास सत्र मात्र नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के संस्कारों की जीवन्त शिक्षा है। युवा संसदीय मर्यादाओं को समझें, जागरूक, विचारशील और उत्तरदायी बनें, लोकतंत्र में मत डालने के साथ राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को सक्रियता से निभाना आवश्यक है।



कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट



राजस्थान के मेरे परिवारजनों को नए एयरपोर्ट की बहुत-बहुत बधाई! हमारी सरकार ने कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने को मंजूरी दी है। इससे देशभर से यहां आने-जाने वालों का हवाई सफर और सुगम होगा, साथ ही पर्यटन एवं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

राजस्थान को बड़ी सौगात

केंद्र सरकार ने कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी देकर राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। इस परियोजना पर 1507 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एयरपोर्ट में 3200 मीटर x 45 मीटर आकार का रनवे, ए-321 प्रकार के विमानों के लिए 07 पार्किंग-बे, दो लिंक टैक्सी-वे, एटीसी-सह-तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन केंद्र और कार पार्क शामिल होंगे। 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में बने टर्मिनल भवन की क्षमता व्यस्त समय में 1000 यात्रियों की होगी जबकि वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की होगी।

राजस्थान सरकार ने इस ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को 440.06 हेक्टेयर भूमि सौंपी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय पर प्रसन्नता जताई और प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान कोटा एयरपोर्ट बेहद सीमित है, जहां सिर्फ 1220 मीटर x 38 मीटर रनवे और 50 यात्रियों की क्षमता वाला छोटा टर्मिनल है। नए एयरपोर्ट से कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री, उद्योग और पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ■



कोटा-बूंदी हवाई अड्डा



शेष भाग – युवा संसद

संसदीय मर्यादाओं में रहकर सार्थक चर्चा

कश्मीर की छात्रा हदीका ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कहा, भारत कश्मीर में स्कूल और अस्पताल बना रहा है, वहीं पाकिस्तान पीओके में बंकर बना रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता-पोसता है यह साबित हो चुका है। भिवाड़ी की जास्मीन ने कहा कि पीओके लेना जरूरी है, लेकिन कश्मीरियों का दिल भी जीतना होगा। जयपुर के प्रणय गुप्ता ने आतंकियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर जोर दिया।

पीओके वापस लेने के प्रस्ताव के पक्ष में शत-प्रतिशत मत

ग्वालियर की दीवा शर्मा ने पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। मुम्बई के छात्र तनय भवेन पारीख ने कहा कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों का बहिष्कार आवश्यक है। जोधपुर के ध्रुव जैन का सवाल था कि दुनिया हमें संयम बरतने की सलाह देती है, हम कब तक हमले सहेंगे? युवा

संसद में पीओके को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस प्रस्ताव को कश्मीरी छात्रा हदीका ने प्रस्तुत किया था। बहस में किसी ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं किया।

युवाओं की संसदीय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के प्रोत्साहन का सशक्त मंच

युवा संसद छात्रों को संसदीय प्रक्रिया और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के बारे में सिखाने का मंच है। इसमें छात्रों को राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर बहस करने, अपने विचार व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है। युवा संसद का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व, सार्वजनिक भाषण कला, गंभीर सोच और नागरिकता की भावना को बढ़ावा देना है। युवा संसद युवाओं को सिर्फ आलोचक नहीं, बल्कि भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे सामाजिक परिवर्तन के वाहक बन सकें। ■

जल-जंगल-जीवन की जननी अरावली

– अमन हरसाना, स्वतंत्र लेखक



कल्पना कीजिए, यदि थार मरुस्थल के तूफानी रेले बिना किसी अवरोध के राजस्थान की धरती पर फैल जाएं, जल स्रोत सूख जाएं और जैव विविधता लुप्त हो जाए, तब इस प्रदेश का जीवन कैसा होगा? यही वह संकट है जिसे सदियों से अरावली पर्वतमाला रोकती आई है।

अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम फोल्डेड माउन्टेन (परतदार या वलित) पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली का नाम संस्कृत शब्द 'आरा' और 'वलि' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'चोटियों की पंक्ति'। इसकी उत्पत्ति लगभग दो अरब से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक पूर्व प्रोटैरोजोइक युग में भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हुई थी। यह तब की बात है, जब हिमालय का कोई अस्तित्व नहीं था। अपने निर्माण के समय अरावली की ऊंचाई हिमालय से भी अधिक थी। निरंतर कटाव और क्षरण के कारण अब यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची है। अरावली को गोण्डवानालैण्ड का हिस्सा भी माना जाता है। गोण्डवानालैण्ड स्वयं एक प्राचीन महाद्वीप था, जिसमें पहले अफ्रीका, दक्षिण अमरीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे वर्तमान भू-भाग भी शामिल थे। यह महाद्वीप कई किलोमीटर नीचे मंथर गति से पास-

दूर होती भू-प्लेटों पर बसे हैं और इनके किनारों के टकराव या दूर जाने, खिसकने से पहाड़ निर्माण और दूसरी कई विशाल भू-रचनाएं बनीं हैं।

अरावली दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर में फैली हुई है। यह पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत की जलवायु, जल-संसाधनों, जैव-विविधता और सांस्कृतिक जीवन को दिशा देती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अरावली केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि जलवायु नियामक, जल-स्रोतों की जननी और जैव विविधता की आश्रय स्थली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू (सिरोही) में गुरुशिखर (1722 मीटर) है तथा इसका सबसे बड़ा और उच्चतम भाग कुंभलगढ़ और गोगुन्दा किलों के बीच पठार के रूप में स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से 'भोराट' कहा जाता है।

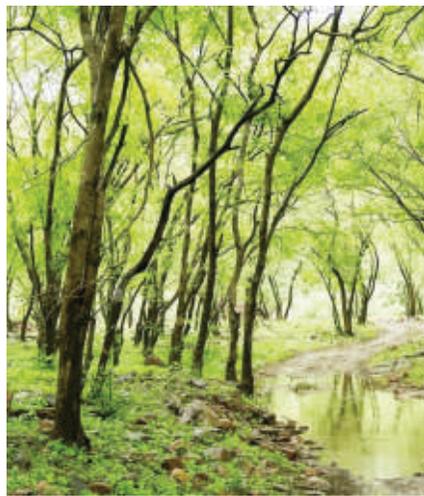
पारिस्थितिक महत्त्व और जलवायु पर प्रभाव

यह पर्वतमाला राज्य के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जलवायु को नियंत्रित करने के साथ-साथ वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की विविधता को भी संरक्षित करती है। अरावली क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण नदियां उद्गम लेती हैं, जिनमें बनास, लूनी और साबरमती शामिल हैं। इस क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की उपस्थिति इसे जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध बनाती है। अरावली क्षेत्र का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जिनमें प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के किले प्रमुख रूप से शामिल हैं।

अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 19 जिलों में फैली हुई है, इनमें प्रमुख रूप से खुला वन (Open Forest), झाड़ी वन (Scrub Forest) शामिल हैं। जलवायु की कठोरता के कारण कुछ जिलों में छोटे झाड़ और कंटीली वनस्पतियां अधिक पाई जाती हैं।

अरावली की वनस्पतियां

अरावली अद्वितीय जैव विविधता से समृद्ध है, जिन में रोहिड़ा (टेकोमेला अंडुलेटा) जिसे राजस्थान का राज्य पुष्प भी कहा जाता है, अपनी सुंदर लकड़ी और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य वृक्ष खेजड़ी (प्रोसोपिस सिनेरिया) जिसे मरुस्थल का जीवनदाता कहा जाता है, इसकी पत्तियां पशुओं के लिए चारा, फल भोजन और लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोगी होती है। कडया (स्टरक्युलिया यूरेन्स) की पत्तियां बहुत पतली और नाजुक होती हैं व पूरे वर्ष के



लिए कुछ महीनों में पर्याप्त भोजन बनाने में सक्षम हैं। धोक (एनोगाइसस पेन्डुला) अरावली के क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में मिलने वाला एक प्रमुख औषधीय वृक्ष है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। तेंदू (डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलॉन) उमदा स्वाद, पत्ते का लचीलापन, काफी समय तक आसानी से नष्ट नहीं होने, और आग को बनाए रखने की क्षमता के कारण इसकी पत्तियों का बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होता है। खैर (सेनेगलिया कैटेचू) की लकड़ी व अर्क का उपयोग विभिन्न औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बबूल (आकास्या नीलोतिका) और अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन) इत्यादि प्रमुख हैं।

अरावली की ये पादप प्रजातियां न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता और स्थानीय समुदायों की आजीविका में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनके संरक्षण से न केवल जैव विविधता को बनाए रखा जा सकता है, बल्कि राजस्थान के पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

प्रकृति और जैव विविधता की संजीवनी

अरावली पर्वतमाला जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां झालाना-आमागढ़ (जयपुर), जवाई बांध (पाली), अमरख महादेव लेपर्ड (उदयपुर), गंगा भेरव घाटी (अजमेर), सुंधामाता (जालोर व सिरोही), मानसा माता (झुंझुनू), बीड़ फतेहपुर (सीकर) जैसे कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए गए हैं। ये क्षेत्र वन्यजीवों के सुरक्षित आवास प्रदान करने के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं।

इसी प्रकार, अरावली की आर्द्रभूमियां जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिनमें सांभर झील, मेनार (उदयपुर), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

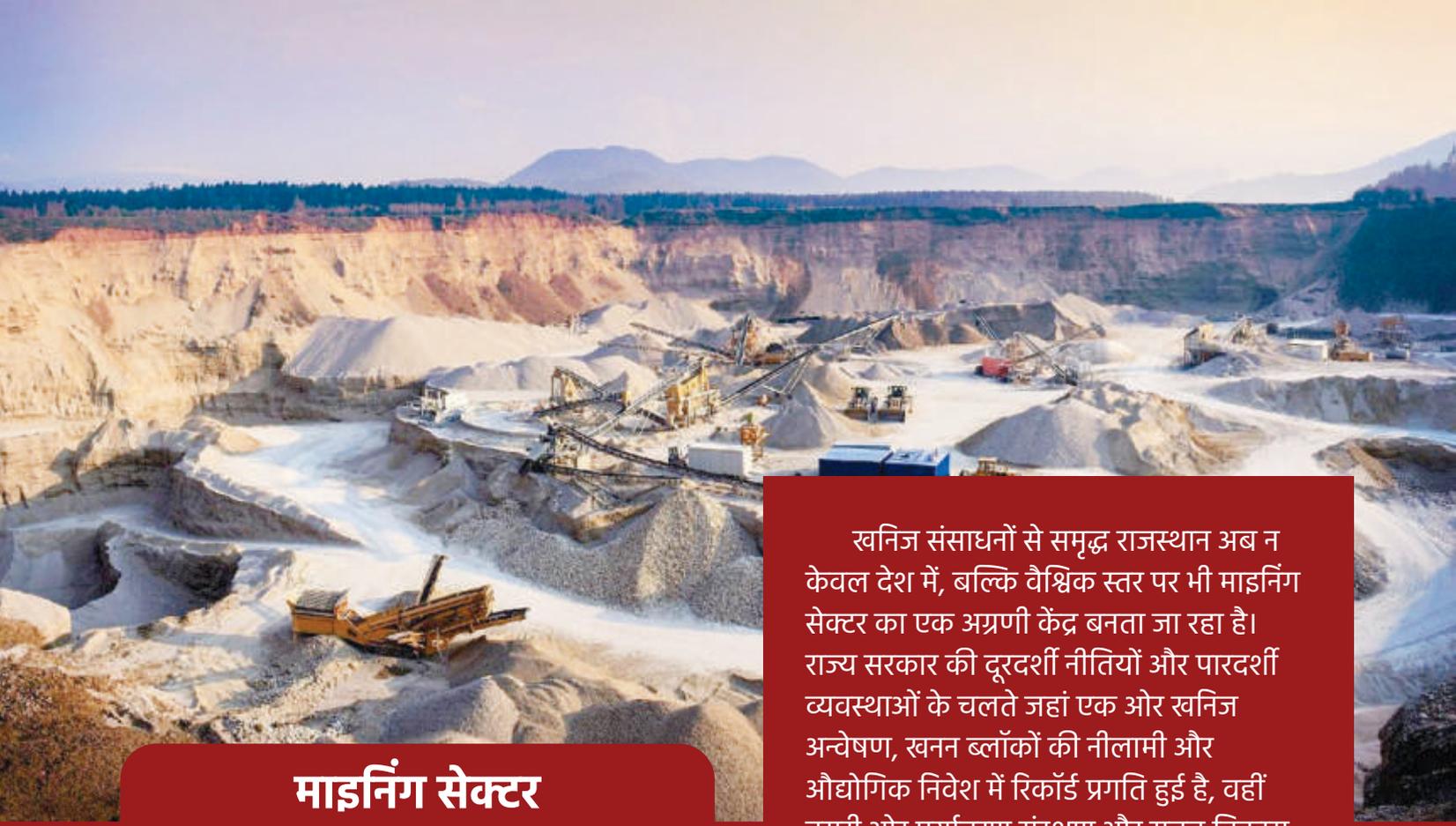
अरावली देववन (ओरण) संरक्षण अभियान

अरावली के पवित्र उपवनों के जीर्णोद्धार के लिए 1992 में उदयपुर वन प्रभाग द्वारा अरावली देववन संरक्षण अभियान (अरावली पवित्र उपवन संरक्षण) कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में उपवनों का संरक्षण, देशी प्रजातियों के पौधे रोपना, मृदा एवं जल संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए सहभागी दृष्टिकोण शामिल थे। पश्चिमी राजस्थान के वीरान जिलों में वृक्षों से भरे विशाल भू-भाग को ओरण कहा जाता है, जो किसी स्थानीय देवी-देवता के नाम से संरक्षित रहते हैं। ये ओरण अरावली के पवित्र उपवनों के समान हैं और इनके लाभ भी समान हैं। राजस्थान सरकार ने 15 मार्च 1991 को पहला संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव जारी किया और संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) शुरू करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक बना। ग्राम स्तरीय वन संरक्षण समितियों के गठन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव के साथ इसे कानूनी रूप दिया गया। जेएफएम कार्यक्रम के तहत सरकार, वन विभाग और स्थानीय वनवासी समुदाय मिलकर वनों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन का कार्य करते हैं।

अरावली ग्रीन वॉल परियोजना

इसका उद्देश्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 1,400 किमी लंबाई और 64.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पांच किलोमीटर चौड़ी 'हरित पट्टी बफर जोन' विकसित करना है। अरावली के कुल अवक्रमित क्षेत्र का सर्वाधिक 81 प्रतिशत राजस्थान में आता है।

परियोजना के लिए राजस्थान सरकार ने 2025-26 के अपने पहले ऐतिहासिक 'हरित बजट' में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसके तहत बंजर भूमि पर करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि मरुस्थलीकरण पर रोक लगे, मृदा स्वास्थ्य सुधरे, भूजल पुनर्भरण हो और जैव विविधता संरक्षित रहे। परियोजना में जलस्रोतों का पुनरुद्धार, कृषि-वानिकी, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएंगे। ■



माइनिंग सेक्टर

खनन में अग्रणी राजस्थान रख रहा पर्यावरण का ध्यान

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, मीडिया प्रभारी, राजस्थान स्टेट गैस लि.

खनिज समृद्धि की ओर बढ़ता राजस्थान

माइनिंग सेक्टर में राजस्थान देश-दुनिया का प्रमुख केन्द्र बन कर उभर रहा है। राजस्थान में 82 प्रकार के मिनरल की उपलब्धता के संकेत मिलते हैं। प्रदेश में 57 मिनरलों की प्रमुखता से खोज और खनन का कार्य चल रहा है। अब राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट (आरईई) के संकेत भी मिलने के साथ राजस्थान तेजी से दुनिया के नक्शे पर उभरा है। राज्य सरकार ने भी माइनिंग सेक्टर को अपनी प्राथमिकता में रखा है। यही कारण है कि राजस्थान माइनिंग सेक्टर में नित नए आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। माइनिंग सेक्टर की महत्ती भूमिका को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में माइनिंग सेक्टर ने खनिज खोज से लेकर माइनर एवं मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन, एमनेस्टी योजना, ड्रोन सर्वे, एकबारीय समाधान योजना, नई और प्रगतिशील खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, पर्यावरण संरक्षण, माइनिंग सेक्टर में औद्योगिक निवेश और रोजगार के विपुल अवसर सृजित करने के अवसर विकसित कर दिए हैं।

इसके साथ ही पारदर्शी व्यवस्था और प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये जा रहे हैं। समय की मांग को देखते हुए ही आरईई और

खनिज संसाधनों से समृद्ध राजस्थान अब न केवल देश में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी माइनिंग सेक्टर का एक अग्रणी केंद्र बनता जा रहा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और पारदर्शी व्यवस्थाओं के चलते जहां एक ओर खनिज अन्वेषण, खनन ब्लॉकों की नीलामी और औद्योगिक निवेश में रिकॉर्ड प्रगति हुई है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए खनन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण और सुरक्षित खनन के प्रावधानों को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार माइनिंग और पर्यावरण के संतुलन को साधते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है।

सैरेमिक आधारित एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो खनिज एक्सप्लोरेशन को गति देने के लिए 'राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन' के गठन की बजटीय घोषणा की गई है। राजस्थान आज देश का माइनिंग सेक्टर में प्रमुख प्रदेश बन गया है। मिनरल एक्सप्लोरेशन से लेकर माइनिंग ब्लॉकों और प्लॉटों के ऑक्शन के क्षेत्र में नित नए आयाम बन रहे हैं, तो निवेश, रोजगार और राजस्व की दृष्टि से राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार ने तय किया कि देश में सभी जगह माइन्स खुले ऑक्शन के माध्यम से ही दी जाएंगी। इससे बहुत हद तक माइनिंग मिनरल्स की बंदर बांट पर रोक लग सकी। केन्द्र सरकार ने मेजर मिनरल्स के ऑक्शन की स्वयं के स्तर पर भी मॉनिटरिंग आरंभ कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाया और खनिज प्रधान प्रमुख राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की राह प्रशस्त की है। इसे देश के खनिज क्षेत्र का अग्रणी कदम माना जा सकता है। मेजर मिनरल के ऑक्शन में पिछले डेढ़ साल में राजस्थान ने तेजी से काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है।



माइनिंग सेक्टर में हरियाली की ओर कदम

राजस्थान योजनाबद्ध तरीके से माइनिंग सेक्टर में आगे बढ़ते हुए वैश्विक पहचान बना रहा है। सुरक्षित खनन के लिए आवश्यक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। प्रदेश में पहली बार 11 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है और पौधारोपण का यह कार्य जारी है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे 'मिशन हरयालो राजस्थान' अभियान के तहत खनन क्षेत्रों व विभागीय कार्यालयों में व्यापक स्तर पर पौधारोपण पर बल देते हुए अगस्त के पहले सप्ताह तक खनन सेक्टर द्वारा 11 लाख 74 हजार से अधिक पौधारोपण करवाया जा चुका है। विभाग अपने स्तर के साथ ही माइनिंग लीज धारकों से समन्वय बनाते हुए पहली बार इतनी अधिक संख्या में पौधारोपण करवाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन व मार्गदर्शन में प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

जीरो लॉस तकनीक और पर्यावरणीय पुनर्भरण के साथ माइनिंग को मिल रही नई दिशा

खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त का कहना है कि राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल खनन को बढ़ावा दे रही है। जीरो लॉस तकनीक अपनाने पर जोर देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और खान सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। खनिज एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाने, अवैध खनन पर कारगर रोक, वैध खनन को बढ़ावा देने, अधिक से अधिक माइनिंग प्लाट तैयार कर ऑक्शन करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर पौधारोपण पर जोर दिया जा रहा है। माइंस विभाग के खनन गतिविधियों से जुड़े होने के कारण पर्यावरण संरक्षण की भी अधिक जिम्मेदारी हो जाती है। प्रत्येक जिले के खनन पट्टा क्षेत्रों में, जहां खनन कार्य पूरा होकर बंद हो चुका है वहां कम से कम एक खान चिन्हित कर उसका पुनर्भरण करवाने और फिर उस स्थान पर व्यापक वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। इससे पहले साल में दो-तीन लाख तक ही पौधारोपण होता था।

“हमें ऐसा खनन मॉडल विकसित करना चाहिए, जो आवश्यकताओं को पूरा करे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बने। खनन उद्योग की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ इसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण का प्रतीक बनाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए।”

– मुख्यमंत्री

खनिज संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण

एमसीडीआर के तहत खनन कार्यों के दौरान वैज्ञानिक विधि से खनिज संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधियां संचालित करने का प्रावधान है। अभियान के दौरान इनकी पालना के साथ ही छोड़ दी गई माइंस के पुनर्भरण एवं माइंस क्लोजर प्लान की पालना के निरीक्षण के प्रावधान है। इसके साथ ही खानों के ओवरबर्डन या वेस्ट आदि निर्धारित स्थान पर रखने और बेक फिलिंग प्रावधानों की पालना भी देखी जाएगी। एमएमआर, 1961 में ओपन कास्ट माइंस की बेंच, हाईट, विड्थ, साइड के स्लोप एंगल, डीप होल ब्लॉस्टिंग और भारी मशीनरी के उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश हैं, ताकि खनन कार्य सुरक्षित व वैज्ञानिक तरीके से हो सके। राज्य सरकार द्वारा ओवरबर्डन का उपयोग एम-सेंड में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई एम-सेंड में यह स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण खान एवं भू-विज्ञान विभाग की प्राथमिकता में आता है और उसी को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर पौधारोपण करवाया जा रहा है। पौधारोपण के दौरान छायादार-फलदार वृक्षों में नीम, बड़, पीपल, आम, शहतूत, शीशम, गुलमोहर, अशोक, जामुन आदि वृक्षों को लगाने पर जोर दिया गया है। पौधारोपण-वृक्षारोपण के दौरान राजस्थान की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार कम पानी और जल्दी बढ़ने वाले वृक्षों और पौधों को लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है। आरंभिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त के मध्य तक माइंस विभाग के 46 कार्यालयों द्वारा 11 लाख 74 हजार 166 पौधे लगवाये जा चुके हैं। 50 हजार से अधिक पौधारोपण वाले कार्यालयों में उदयपुर में 72,082 पौधे, राजसमंद में 66,502 पौधे, भीलवाड़ा में 53,254 पौधे, ब्यावर में 51,530 पौधे और नागौर में 49,772 पौधे लगाये जा चुके हैं। समूचे प्रदेश में पौधारोपण का कार्य जारी है। विभाग द्वारा पौधारोपण के साथ ही मानसून सीजन के दौरान लगाये जाने वाले पौधों व वृक्षों के रखरखाव और सार-संभाल की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों व संस्थाओं को दी है, ताकि पौधारोपण अभियान अपने उद्देश्यों में पूरा हो सके। ■



कान्हा के वचन, गीता के आदर्श विकास यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक

“भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश हर युग में प्रासंगिक एवं पथ प्रदर्शक हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म करने, अन्याय का प्रतिकार करने तथा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का संदेश दिया। भगवान श्रीकृष्ण के महान आदर्शों को आत्मसात करें और देश-प्रदेश की प्रगति में सहभागी बनने का संकल्प लें।”

– मुख्यमंत्री



जयपुर जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भक्ति और उत्साह के रंगों में सराबोर रहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सपत्नीक विभिन्न मंदिरों में दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और आमजन की खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री ने 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर जयपुर के आराध्य देव श्री गोविन्द देव जी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के गीता उपदेश आज भी हमारे जीवन को सार्थक बना रहे हैं। कर्मप्रधानता के उनके संदेश को आत्मसात कर हम सभी को विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात श्री शर्मा ने जयनिवास बाग स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में भी दर्शन किए और मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया।



इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सपत्नीक मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए और श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में श्री गिरिधारी दाऊजी, श्री राधा मदनमोहन एवं श्री गौर नितार्ई की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृष्ण भक्ति कीर्तन में भाग लिया और श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद किया। पूरे मंदिर परिसर में गूँजते मधुर कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो उठा।

गोविन्द देव जी मंदिर से शोभायात्रा का शुभारंभ

जन्माष्टमी के दूसरे दिन मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने श्री गोविन्द देव जी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने रथ में विराजमान गोविन्द देव जी के चित्रस्वरूप की पूजा कर आरती की और प्रदेश में सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। परिसर में पहुंचने पर मंदिर महंत ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद, विधायक, महापौर सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

भाई का वचन, बहन की आस

राखी

रही इस बार खास

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर छात्राओं, महिला पत्रकारों, विशेष योग्यजन बहनों, वीरांगनाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर भावनात्मक जुड़ाव व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षासूत्र में बहनों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद समाया होता है, जो उनके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है और उन्हें नई ऊर्जा से कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में भाई-बहन का रिश्ता अत्यंत स्नेहपूर्ण होता है और बहनें अपने भाई की दीर्घायु और उन्नति की कामना करती हैं। बहनों ने मुख्यमंत्री निवास पर आकर राखी बांधने को अपने मायके जैसा अनुभव बताया और महिला सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। कार्यक्रम में पारंपरिक लोकगीत भी गाए गए।





संस्कृति से प्रकृति तक

भारतीय पौराणिक वाङ्मय, धर्मग्रंथों, आख्यानों एवं चिन्तन परम्परा में पर्यावरण संरक्षण

- डॉ गोरधन लाल शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा



हमारे पौराणिक ग्रन्थों में जल - जंगल - जमीन, जीव-जन्तु और जलवायु सहित सम्पूर्ण पर्यावरण संरक्षण का गहन चिन्तन निहित है। संस्कृत में कहा भी गया है....

ॐ

**परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः,
परोपकाराय वहन्ति नद्यः।
परोपकाराय दुहन्ति गावः,
परोपकारार्थं मिदं शरीरम् ॥**

ॐ

अर्थात् वृक्ष फल देते हैं, नदियां बहती हैं, गायें दूध देती हैं और यह शरीर भी दूसरों की सेवा के लिए है। यह श्लोक प्रकृति के परोपकारी स्वरूप को दर्शाता है और बताता है कि हमें भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में कार्य करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों, नदियों, वायु, जल और अग्नि को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती रही है। पीपल, वट और तुलसी जैसे पौधों को पवित्र माना गया है। वेद, पुराण, उपनिषद तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में पेड़-पौधों, वन्य जीवन और उनके महत्त्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में वृक्षों की कटाई जैसे कार्यों पर दंड का प्रावधान था, जिससे पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में भी साफ-सफाई, वृक्षों की पूजा और पर्यावरण संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं। आर्य सभ्यता में वैदिक ऋषियों ने अरण्यों की रक्षा की है। यजुर्वेद में कहा गया है कि वृक्षों को न काटो, जल और पृथ्वी की रक्षा करना धर्म है। यह भूमि माता के समान पोषण करने वाली है और मनुष्य पुत्र की भांति इसका रक्षक है। लोक परंपराओं में भी पौधों का विशेष महत्त्व रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण की भावना भारतीय जनमानस में रची-बसी रही है।



भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण

भारतीय संविधान के भाग 4-ए, अनुच्छेद 51-ए में प्रत्येक नागरिक के लिए पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य बताया गया है। सृष्टि के आरंभ से ही मानव और प्रकृति का गहरा संबंध रहा है, जहां धरती समस्त जीवों का पालन करती आई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, “क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम सरीरा” अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन्हीं पांच तत्वों से मानव शरीर बना है और इनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं। परंतु आज विकास के नाम पर मानव ने प्रकृति को क्षति पहुंचाकर पर्यावरण को संकट में डाल दिया है। अतः अब आवश्यक है कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाकर स्थायी विकास की ओर बढ़ा जाए।

पर्यावरण संरक्षण का संस्कार अखण्ड भारतभूमि में ही देखने को मिलता है, जहां सनातन परम्पराओं में प्रकृति संरक्षण के स्पष्ट सूत्र निहित हैं। हिन्दू धर्म में प्रकृति पूजन को संरक्षण का माध्यम माना गया है, जिसमें पेड़-पौधे, नदी-पर्वत, अग्नि-वायु, ग्रह-नक्षत्र आदि प्रकृति के विविध रूपों के साथ मानवीय संबंध जोड़े गए हैं। पेड़ को संतान, नदी को मां, वायु, अग्नि, पर्वत और ग्रह-नक्षत्रों को देवस्वरूप मानकर उनकी आराधना की गई है। प्राचीन काल में भारत के ऋषि-मुनियों को प्रकृति और मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। वे जानते थे कि मनुष्य क्षणिक लाभ के लिए ऐसी भूल कर सकता है, जिससे उसका ही बड़ा नुकसान हो, इसलिए उन्होंने प्रकृति से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया ताकि उसे क्षति पहुंचाने से रोका जा सके। भारत में सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की परंपरा रही है, जिसमें पेड़, जल, पर्यावरण, पशु-पक्षियों और पृथ्वी की रक्षा का भाव निहित है। बावजूद इसके, आज भौतिक विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति उपेक्षित हुई है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि

यदि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं न होतीं, तो भारत की स्थिति भी पश्चिमी देशों की तरह गंभीर पर्यावरणीय संकट में होती। हिन्दू परंपराओं ने अनेक स्तरों पर प्रकृति का संरक्षण किया है, जिसका प्रमाण है कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि की स्तुति में समर्पित है, जो प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाता है।

पर्यावरण संरक्षण - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जहां हड़प्पा संस्कृति प्रकृति से ओत-प्रोत थी और वैदिक संस्कृति पर्यावरण संरक्षण की प्रतीक रही। भारतीय मनीषियों ने सूर्य, जल, नदियों और वृक्षों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा की, जिससे प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान विकसित हुआ। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुईं और पीपल, तुलसी, बरगद जैसे वृक्ष पूजनीय बने। मध्यकाल और मुगलकाल में भी यह भाव बना रहा, किंतु अंग्रेजों के आर्थिक शोषण और अंधाधुंध दोहन से पर्यावरणीय असंतुलन शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद पश्चिमी प्रभाव, औद्योगीकरण और जनसंख्या विस्फोट ने प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा दिया।

वेद एवं वेदांत में पर्यावरण की अलख

वेद, वेदांत और अन्य शास्त्रीय हिंदू ग्रंथों में प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति गहन चेतना का परिचय मिलता है, जहां पेड़-पौधों, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष और पृथ्वी को न केवल जीवनदायिनी तत्व माना गया, बल्कि उन्हें देवतुल्य सम्मान भी दिया गया। ऋग्वेद (1.23.248) में जल को अमृत और औषधीय गुणों से युक्त बताया गया है, “अप्सु अन्तः अमृतं, अप्सु भेषजं”। वहीं यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया को वायुमंडल की शुद्धि और स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा गया है। अथर्ववेद ‘देने और लेने के संतुलन पर जोर देता है, जिससे जल स्वच्छता, वन्यजीव संरक्षण और मवेशियों के पालन-पोषण जैसे पर्यावरणीय पक्षों की





समझ मिलती है। सामवेद मौसमी चक्रों के संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जबकि ऋग्वेद में ओजोन परत जैसी रक्षात्मक संरचना के संकेत भी मिलते हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के श्लोक “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः” जैसे वैदिक श्लोक वृक्षारोपण के पुण्यफल और अच्छे लोकों की प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। चाणक्य के न्यायशास्त्र में जंगलों की रक्षा हेतु कठोर दंड का विधान था, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। रामायण और रामचरित मानस में भी प्रकृति की विशुद्धता पर बल देते हुए जीव-जंतु एवं वनस्पतियों से प्रेम का संदेश दिया गया है। महाकाव्य रामायण में रावण आपदा का सामना करने पर कहता है “मैंने वैशाख में अंजीर का वृक्ष नहीं काटा, फिर यह दुर्भाग्य क्यों?” हमारे मुनि ऋषियों ने उद्घोष किया है - ‘ओम द्यो शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः, पृथ्वी शान्तिः, आपः शान्तिः।’ इस प्रकार नैसर्गिक रूप से मनुष्य अपने मन, वचन तथा आचरण एवं व्यवहार से प्रकृति के प्रकोप को शांत करके ही अपना जीवन सुखी और शांत बना सकता है।

कालिदास ने हिमालय को आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना, जबकि महाभारत में प्रकृति के मूल तत्वों को शरीर के अंगों से जोड़कर मनुष्य और प्रकृति के अभिन्न संबंध को दर्शाया गया है। विष्णु पुराण में ब्रह्मांड को बरगद के बीज में समाहित बताकर प्रकृति की विराटता का चित्रण किया गया है। हिन्दू धर्म का मूल संदेश यही है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच माता-पुत्र जैसा संबंध है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वृक्षारोपण व संरक्षण को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में स्थापित किया गया है।

श्रीमद्भागवद् गीता में पर्यावरण सुरक्षा के मंत्र

श्रीमद्भागवद् गीता में भगवान कृष्ण ने संसार की तुलना एक अनंत शाखाओं वाले बरगद के वृक्ष से की है, जिसमें सभी प्राणी, मानव, पशु और देवता विचरण करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चिंतन प्रकृति और वनों से परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण श्रीमद्भागवद् गीता (9.26) में कहते हैं “पात्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मेय भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्त युपहतम असनामि प्रयतात्मनः।” अर्थात् मैं एक पत्ता, फूल, फल या जल या जो कुछ भी भक्तिपूर्वक अर्पित किया जाता है, उसे स्वीकार करता हूँ। जिससे यह संदेश मिलता है कि प्रकृति के अंश भी पूजा में पवित्र माने जाते हैं। वैदिक मंत्र



“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चि जगत्यां जगत्” यह दर्शाता है कि समस्त जगत में ईश्वर का वास है। अतः प्रकृति का सम्मान और संरक्षण आवश्यक है। हिन्दू पूजा पद्धति में नारियल, आम के पत्ते, पुष्प, तुलसी और कमल जैसे पौधों का विशेष धार्मिक महत्व है, जो पर्यावरण के प्रति श्रद्धा को दर्शाते हैं। “पवनः दुष्टतां याति प्रकृति विकृतायते” जैसे श्लोक प्रदूषण से उत्पन्न पर्यावरणीय असंतुलन की ओर संकेत करते हैं। प्राचीन हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध, जैन, सिख और अन्य सनातन परंपराओं में भी पर्यावरण संरक्षण को धार्मिक कर्तव्य के रूप में स्वीकारा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना सभी धर्मों का साझा उद्देश्य रहा है।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और प्रकृति के महत्व को हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेक संस्कृत श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिनमें पृथ्वी, जल, वायु और वनस्पतियों जैसे प्राकृतिक तत्वों को विशेष स्थान दिया गया है। उदाहरणस्वरूप, “यथा वृक्षाणां रोपणं पुण्यं लभ्यते तथा जलस्य रक्षणं जीवनं रक्षति” यह श्लोक पेड़ लगाने और जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है, इसलिए हमें वृक्षारोपण, मिट्टी की रक्षा, जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत खोजने जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे। अतः अपनी प्राचीन परंपराओं को पुनः अपनाकर प्रकृति संरक्षण को अपनी संस्कृति और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना अत्यंत आवश्यक है। ■



राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 23 अगस्त, 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप 'विकसित राजस्थान@2047' विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई। इस दस्तावेज़ में वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं युवा सशक्तीकरण, शत-प्रतिशत साक्षरता, सतत जल प्रबंधन, हरित ऊर्जा, स्मार्ट शहरीकरण, किफायती आवास और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप विभागवार कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी और चरणबद्ध तरीके से इसका क्रियान्वयन होगा।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना

बैठक में युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अधिकतम दो करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर आठ प्रतिशत तक ब्याज अनुदान मिलेगा। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों और बुनकर/शिल्पकारों को अतिरिक्त अनुदान की सुविधा रहेगी। ऋण पर पच्चीस प्रतिशत अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा।

इसी तरह मंत्रिमंडल ने नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और एकरूप बनाया जाएगा। विभिन्न सामाजिक उपयोगों हेतु भूमि आवंटन डीएलसी दर के 40 प्रतिशत पर किया जाएगा, जबकि राजकीय विभागों को निःशुल्क भूमि मिल सकेगी। नई नीति से भूमि आवंटन नीति-2015 को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने और एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को भी मंजूरी दी गई। इस नीति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी।

कैबिनेट ने जयपुर में 95 एकड़ भूमि पर लगभग 3700 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आईटी टावर विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। यह परियोजना एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से पूरी होगी, जिसमें लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपये की लागत से विशाल कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। बैठक में रिम्स की स्थापना, एक्सप्रेसवे शुल्क दर संशोधन, कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025, मत्स्य संशोधन विधेयक-2025, सेवा नियमों में बदलाव और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1283 हेक्टेयर भूमि पर 2400 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने जैसे फैसले भी किए गए। साथ ही, जनजातीय क्षेत्रों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन तथा परवन बांध डूब क्षेत्र के विस्थापित परिवारों को विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया गया। ■



सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ता राजस्थान

मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय

राजस्थान में विकास, सुशासन और आमजन को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 31 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिनमें ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विस्तार, सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति में संशोधन और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कठोर विधेयक सम्मिलित रहे। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी।

नगरीय निकायों में 2 लाख नई स्ट्रीट लाइटें

राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि बजट 2025-26 में एक लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 हो गई है और कई पुराने लाइटें बदलने की आवश्यकता भी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक लाख के स्थान पर दो लाख नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना पर लगभग 160 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

राजसेस महाविद्यालयों में भर्तियां

राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राजसेस) का गठन वर्ष 2020 में किया गया था। इसके अंतर्गत वर्तमान में 374 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक और 5,295 अशैक्षणिक पद शामिल हैं। फिलहाल ये सभी पद रिक्त हैं और शिक्षण कार्य "विद्या संबल योजना" के तहत करवाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 4,724 संविदा पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इनमें 3,540 शैक्षणिक पद होंगे, जिन पर यूजीसी मापदंडों के अनुसार योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा पैटर्न, भर्ती एजेंसी और

राजसेस हायरिंग ऑफ मैनुअल वर्कर रूल्स 2023 में संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है।

सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति में संशोधन

बैठक में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई भी पानी नालियों या सड़कों पर न बहे। पुराने नेटवर्क के कारण आने वाली समस्याओं को देखते हुए यह संशोधन आवश्यक हो गया था। संशोधित नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप होगी। इसके तहत सभी नगरीय निकायों में सुव्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था स्थापित की जाएगी और शोधन उपरान्त प्राप्त जल, खाद और गैस का पुनः उपयोग किया जाएगा। नई नीति में "हैम मॉडल" को अपनाया गया है। इसके अनुसार परियोजना लागत का 40 प्रतिशत भाग कार्य पूर्ण होने पर और शेष 60 प्रतिशत राशि संचालन एवं संधारण अवधि के दौरान समान किशतों में निजी भागीदार को दी जाएगी।

राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025

राजस्थान सरकार ने प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। मंत्रिमंडल बैठक में "राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025" के नए प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत मिथ्या निरूपण, कपट, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव डालकर किए गए धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन कराता है, तो वह विवाह शून्य माना जाएगा।

विधेयक के अनुसार न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नाबालिग, महिला, एससी-एसटी वर्ग के मामलों में यह सजा 10 से 20 वर्ष तक हो सकती है और न्यूनतम जुर्माना 10 लाख रुपये होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। यदि धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी अथवा अवैध संस्थानों से धन लिया जाता है, तो 10 से 20 वर्ष की सजा और न्यूनतम 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि अपराध की पुनरावृत्ति होती

है, तो आजीवन कारावास और न्यूनतम 50 लाख रुपये का जुर्माना होगा। साथ ही, ऐसे मामलों में दोषी संस्था का पंजीकरण रद्द किया जाएगा, सरकारी अनुदान बंद होगा और धर्म परिवर्तन की घटना स्थल की संपत्ति जब्त की जा सकेगी।

विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति और संशोधन

राजस्थान लोक सेवा आयोग में अन्वेषणकर्ता (सांख्यिकी सहायक) का पदनाम बदलकर "सहायक सांख्यिकी अधिकारी" किया गया है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। कारागार विभाग में "वरिष्ठ प्रहरी" के पद को विलोपित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की अनुसूची में "अतिरिक्त निदेशक" का पद जोड़ा गया है। भू-जल विभाग में अधीक्षण भू-भौतिकविद और अधीक्षण रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित

किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियम

राज्य सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए सेवा नियमों को मंजूरी दी। वर्ष 2014 में बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन अब तक सेवा नियम नहीं बनाए गए थे। नई अधिसूचना के अंतर्गत "राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैजेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स, 2025" और "राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्टीरियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स, 2025" लागू किए जाएंगे। साथ ही, "राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) रूल्स, 2022" में संशोधन भी स्वीकृत किया गया है। ■



घरेलू बिजली उपभोक्ता अब बनेंगे ऊर्जादाता

राजस्थान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। प्रदेश में जल्द ही "पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना" लागू की जाएगी। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर प्रतिमाह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती थी, लेकिन इस नई पहल से यह लाभ बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है। इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा।

बजट 2025-26 में की गई थी घोषणा

वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को और सशक्त बनाने के लिए इसे "पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" से जोड़ने की घोषणा की गई थी। बजट में यह भी कहा गया था कि जिन परिवारों के पास पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे, ताकि वे भी योजना का लाभ उठा सकें।

150 यूनिट से अधिक उपभोग वाले परिवारों के लिए ...

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत ऐसे 27 लाख परिवार, जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार अतिरिक्त 17,000 रुपये की सहायता देगी। इस प्रकार एक संयंत्र पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इन सोलर पैनलों से उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और उनका मासिक बिजली बिल शून्य होगा। इन 27 लाख परिवारों की छतों पर संयंत्र लगने से लगभग 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता का सृजन होगा।

150 यूनिट से कम उपभोग वाले उपभोक्ताओं के लिए ...

150 यूनिट से कम मासिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे 11 लाख परिवार आते हैं, जिनके पास अपनी छत उपलब्ध है। इनके घरों पर डिस्कॉम्स के माध्यम से 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र निःशुल्क लगाए जाएंगे। दूसरी श्रेणी में वे परिवार शामिल होंगे, जिनके पास अपनी छत नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र स्थापित करेंगे। इन संयंत्रों से प्राप्त बिजली उपभोक्ताओं को वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से दी जाएगी और उन्हें 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। सामुदायिक संयंत्रों का सम्पूर्ण खर्च डिस्कॉम्स वहन करेंगे।

राज्य सरकार की इस पहल को सफल बनाने और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इनमें 150 यूनिट से अधिक और 150 यूनिट से कम उपभोग करने वाले दोनों ही श्रेणियों के 5-5 लाख उपभोक्ताओं के बैंक खातों में डिस्कॉम्स द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 1100 रुपये की राशि भेजी जाएगी। ■

मेल-मुलाकात



मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। साथ ही केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी, केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिनों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से शिष्टाचार भेंट कर राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।



बैठकें

नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों 'भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम' के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से न्यायिक व्यवस्था के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत हुआ है और राजस्थान को इनके सफल क्रियान्वयन में देशभर का रोल मॉडल बनना है। बैठक में कोर्ट, कारागार, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित करने, राजकॉप ऐप पर महिलाओं के लिए 'नीड हैल्प' सुविधा और नागरिकों के लिए एसओएस अलर्ट जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने, अभियोजन प्रकरणों की निगरानी, फॉरेंसिक लैब का आधुनिकीकरण, पर्याप्त मानव संसाधन की नियुक्ति तथा पुलिस स्टेशनों में राजनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चयनित मॉडल जिलों में अगले तीन माह में नए कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

भरतपुर में विकास कार्यों को गति देने के निर्देश

भरतपुर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने फेज-1 के सभी कार्यों को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों, ड्रेनेज, चौराहों के सौन्दर्यीकरण, मंदिरों के पुनरुद्धार और पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही, केवलादेव उद्यान के लिए नया एंटी प्लाजा, भूमिगत केबलिंग, सुजान गंगा की शुद्धि, कॉलेज ग्राउंड में खेल सुविधाएं और मास्टर ड्रेनेज कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने नए अस्पतालों के निर्माण, नियमित मॉनिटरिंग और बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन पर जोर दिया। 6.2 करोड़ से अधिक आभा आईडी के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है और 1.68 करोड़ से अधिक ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनाए गए हैं। आरयूएचएस को रिस्स के रूप में विकसित करने के लिए 750 करोड़ रुपये चरणबद्ध रूप से खर्च किए जाएंगे। आरजीएचएस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग रोकने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए घर पर दवा वितरण के पायलट प्रोजेक्ट, अस्पतालों का सुदृढीकरण, रिक्त पदों पर लगातार भर्ती और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों तथा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य को जल उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को जल उपलब्धता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट भेजने



और तय समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। राम जल सेतु लिंक परियोजना को महत्वाकांक्षी बताते हुए उन्होंने इसकी प्रगति धरातल पर दिखाने पर जोर दिया। बैठक में राणा प्रताप सागर-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध, बीसलपुर से बाणगंगा और रूपारेल नदी जोड़ने सहित अन्य परियोजनाओं की समीक्षा हुई। उन्होंने 3,236 छोटे बांधों के प्रबंधन के लिए मनरेगा से समन्वय, लंबित बजटीय घोषणाओं, एनआईटी, टेंडर और डीपीआर को तय समय पर पूरा करने को भी कहा।

निवेश क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश

'राइजिंग राजस्थान' एमओयू समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान वैश्विक स्तर पर बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के रूप में उभर रहा है। 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनसे बुनियादी ढांचे का विकास और रोजगार सृजन होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमओयू से जुड़े भूमि आवंटन सहित कार्यों को समयबद्ध पूरा करें और निवेशकों से निरंतर संवाद बनाए रखें। छोटे निवेश समझौतों को भी प्रदेश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

ट्रैफिक व्यवस्था हो सुगम और दीर्घकालीन

मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को तुरंत सुगम और दीर्घकालीन बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने गृह, यातायात, जेडीए, शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग को सामूहिक जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों व आमजन से सुझाव लेकर व्यस्त मार्गों पर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था विकसित की जाए। चिन्हित बस-ऑटो स्टैंड का स्थानांतरण शीघ्र लागू किया जाए तथा

हीरापुरा बस टर्मिनल से मानसून के बाद बसों का संचालन शुरू किया जाए। साथ ही, नए बस स्टैंड से यात्रियों की सुविधा हेतु जेसीटीसीएल बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मल्टीलेवल पार्किंग व्यवस्था, जोन आधारित ई-रिक्शा संचालन और जब्त ई-रिक्शाओं के लिए यार्ड विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही, आरटीआईडी फंड से आधुनिक कैमरे व कंट्रोल रूम स्थापित कर नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

विद्युत तंत्र सुदृढ़ कर निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान में विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए, ताकि घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक दिन में किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में उत्पादन इकाइयों के रख-रखाव, ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत, कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने, गांव-ढाणी तक बिजली पहुंचाने के लिए जीएसएस निर्माण, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने राजस्व बढ़ाने, छीजत रोकने, खराब मीटरों पर जिम्मेदारी तय करने, लापरवाह कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए। साथ ही, पम्प स्टोरेज, कोयला, गैस, जल विद्युत परियोजनाओं और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर चर्चा की गई।

गांव से कस्बों तक खेल सुविधाओं का हो विस्तार

युवा मामले एवं खेल विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करने और श्रेष्ठ खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के सफल आयोजन की प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन से प्रदेश में खेलों का माहौल बनेगा। खिलाड़ियों के

आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं की सर्वोत्तम व्यवस्था हो। आयोजन जयपुर सहित अन्य जिलों में कराने पर विचार किया जाए तथा विभाग परस्पर समन्वय से कार्य करें। श्री शर्मा ने युवाओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने, श्रेष्ठ खेल मैदानों का चयन करने, पंचायत से जिला स्तर तक खेल वातावरण तैयार करने और विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए। "वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट" योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक खेल को बढ़ावा दिया जाएगा और खेल विशेषज्ञों को संयोजक बनाकर प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी।

पर्यटन बनेगा प्रदेश की विकास गाथा का अहम अध्याय

पर्यटन व कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों पर उच्च स्तरीय आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जाएं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को कार्ययोजना बनाकर तय समय पर पूरा किया जाए और जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों के सुझावों को विकास कार्यों में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने संग्रहालयों के उन्नयन, पैनोरमा निर्माण, बावड़ियों के जीर्णोद्धार जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया और हर तीन माह में इनकी प्रगति की मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर व घाटों के विकास, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीपीआर तैयार करने तथा वॉटर व डेजर्ट एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नई ऊंचाइयाँ देने के लिए विशेष योजना बनाई जाए। साथ ही, उदयपुर व जोधपुर में ट्रेवल मार्ट आयोजित करने तथा बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बीगोद संगम को जोड़ते हुए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग की ओर से डेढ़ वर्ष में पर्यटन स्थलों पर हुए विकास कार्यों पर आधारित वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ■

राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, जयपुर शाखा द्वारा आयोजित 'एआई इनोवेशन समिट 2025' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट देश की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने सीए से राज्य व देश की प्रगति में अधिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक सीए राजस्थान से हैं और बदलते नियमों व तकनीकों को समाज तक सही रूप में पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2014 में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि एआई केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति है, जिसमें भारत तेजी से पहचान बना रहा है। राजस्थान भी डिजिटल इंडिया और इंडिया एआई मिशन के साथ नई एआई व मशीन लर्निंग पॉलिसी पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने 'प्राइव्सी इन एआई' पुस्तक, समिट की स्मारिका का विमोचन और 'एआई 2.0 कोर्स' का ऑनलाइन शुभारंभ किया।

आत्मनिर्भर किसान, राजस्थान की पहचान



केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान कार्यक्रम में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान भारत की आत्मा। उन्होंने राजस्थान सरकार को कृषक कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए बधाई दी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान देश का गौरव है और हमारी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर व ऊर्जादाता बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 7.04 करोड़ फसल बीमा पॉलिसी जारी हुई और 1.48 करोड़ किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। इस अवसर पर रबी 2024-25 व खरीफ 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी से किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रदेश के 9.7 लाख किसानों को 1426 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, जबकि देशभर में 34.48 लाख किसानों को लाभ मिला।

हर गांव-ढाणी तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पित

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। वर्ष 2027 तक पूरी होने वाली इस परियोजना से 302 गांवों की लगभग 5.58 लाख आबादी और लालसोट की करीब 69 हजार आबादी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में पानी, बिजली, सिंचाई और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए गए हैं। किसानों को 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 82,964 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दी है और 8,496 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कार्यक्रम में 32 हजार से अधिक फार्म पौंड, लगभग 4,800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता, 1,421 गांवों को सड़क से जोड़ना, 89 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट और पौने दस लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। लालसोट विधानसभा के लिए 116 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेजों का उन्नयन शामिल है।

ई-साइकिल संग बढ़ेगा बेटियों का आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ई-साइकिल वितरण समारोह में कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण और उत्थान को प्राथमिकता मानकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों के शिक्षित व सशक्त होने से ही समाज और देश सशक्त होगा। मुख्यमंत्री ने बालिकाओं से आत्मीय संवाद किया। छात्राओं ने कहा कि ई-साइकिल से पढ़ाई आसान होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आवागमन में समय व पैसे की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने भी अपने छात्र जीवन का अनुभव साझा किया।



श्री शर्मा ने बताया कि अब तक गार्गी पुरस्कार योजना से 3.90 लाख बालिकाएं, बालिका प्रोत्साहन योजना से 2 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। लाडो योजना के तहत गरीब परिवारों को बालिका जन्म पर 1.50 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 11 लाख से अधिक छात्राओं को साइकिल दी जा चुकी है। महिला सशक्तीकरण हेतु मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (बढ़ी हुई राशि 6,500 रुपये) और मातृत्व पोषण योजना लागू हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बालिकाएं और कामकाजी महिलाएं उपस्थित थीं।

विकसित भारत की यात्रा में नया मील का पथर

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने बालोतरा के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी (एचआरआरएल) का निरीक्षण किया। उन्होंने कूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू), डि्लेयड कोकिंग यूनिट (डीसीयू) और रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम (आरएमसीआर) का उद्घाटन किया। साथ ही ऑपरटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी अस्पताल शीघ्र शुरू करने, उत्पाद बिक्री योजना बनाने, सौर ऊर्जा एवं बैटरी स्टोरेज की संभावनाएं तलाशने और परिसर में पौधारोपण बढ़ाने पर जोर दिया। राज्य व केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से पिछले छह माह में रिफाइनरी कार्यों में तेजी आई है। यह परियोजना युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।





सुजस प्रश्नोत्तरी

प्रश्नोत्तरी नं. - 02

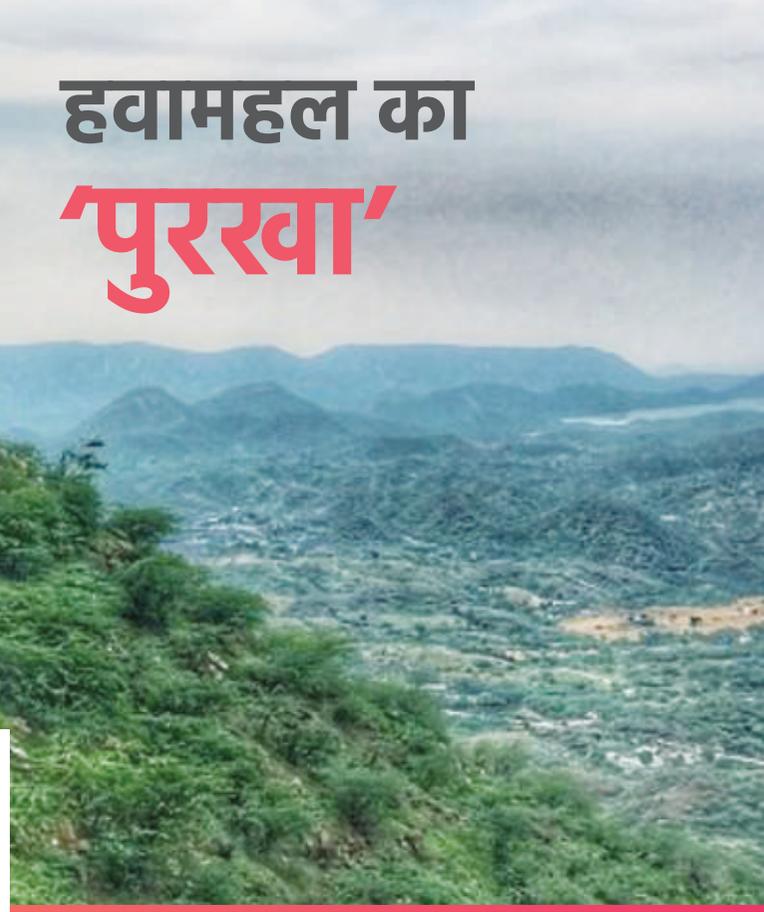
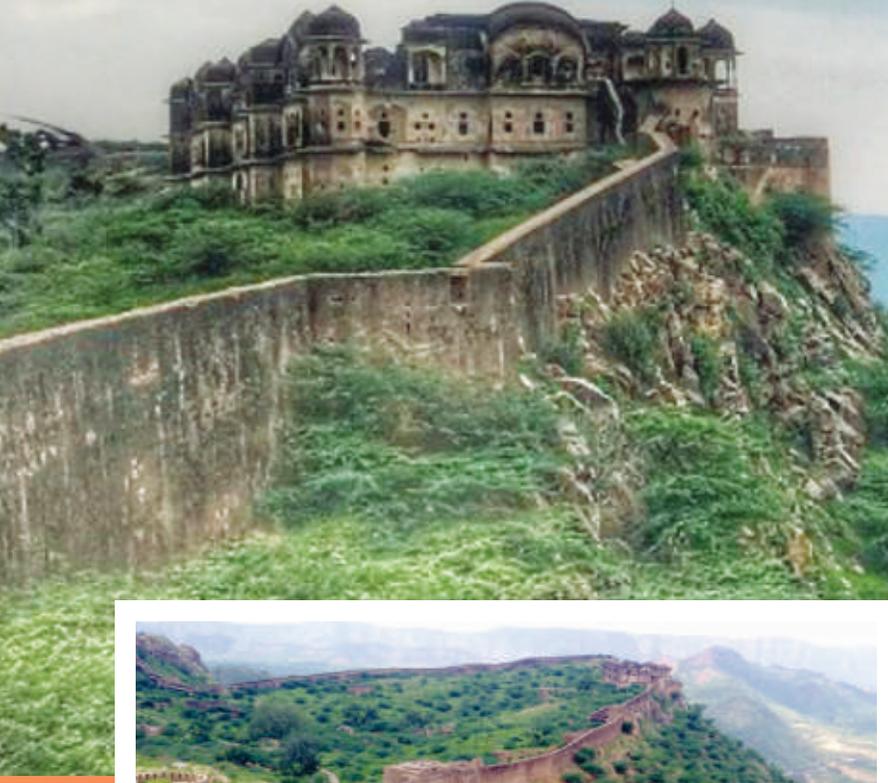
01. राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहाँ देखी गई?
a) टोंक b) जयपुर c) झालावाड़ d) अलवर
02. नागौर जिले के दधिमती माता मंदिर के सभामंडप के गोवर्धन स्तंभ लेख की लिपि कौनसी है?
a) गुजराती b) ब्राह्मी c) खरोष्ठी d) मुड़िया
03. निम्न में से भक्त कवि-रचना का कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है।
a) हरिदास जी : केलिमाल b) नाभादासजी : अष्टयाम
c) दादूदयालजी : हरडेवानी d) मीराबाई : गीत गोविन्द
04. असाध्य बीमारियों से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में खोले गये वार्ड का नाम क्या है?
a) गोविन्दाश्रय वार्ड b) रामाश्रय वार्ड
c) पिताश्रय वार्ड d) दीनाश्रय वार्ड
05. निम्न में से किस खनिज भंडार में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है?
a) फेल्डस्पार b) टंगस्टन c) फ्लुओराइट d) सोना
06. राजस्थान की निम्न में से किस महिला तैराक (swimmer) को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
a) वर्षा सोनी b) मंजरी भार्गव
c) सुनीता पुरी d) भुवनेश्वरी कुमारी
07. महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था?
a) जयवंताबाई सोनगरा b) हाड़ी रानी सहल कंवर
c) उमादे भटियाणी d) सौभाग्य देवी
08. रोहिड़ा वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है?
a) Prosopis Cineraria b) Tecomella Undulatta
c) Azadiracta Indica d) Salvadora Persica
09. निम्न में से सांपों की कौनसी प्रजाति सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाई जाती?
a) Indian Krait b) Russell's Viper
c) Spactacled Cobra d) Bamboo Pit Viper
10. जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (DMFT) निधि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं किया जा सकता?
a) स्वास्थ्य देखभाल b) पर्यावरण संरक्षण
c) वृद्ध व निशक्तजन कल्याण d) सामाजिक सुरक्षा पेंशन
11. निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तहसीलों की संख्या सबसे कम है?
a) सलूमबर b) डीग c) सिरोही d) बालोतरा
12. निम्न में से किस राजस्थानी उत्पाद को G.I. Tag नहीं मिला है?
a) बीकानेर उस्ता कला b) बीकानेरी भुजिया
c) सोजत मेहंदी d) शेखावाटी बंधेज
13. यहूदियों का पूजा स्थल बेदखबाद राजस्थान के किस नगर में है?
a) उदयपुर b) जयपुर c) फलोदी d) पुष्कर
14. जयपुर पुलिस द्वारा नौकर - किरायेदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु जारी किये मोबाइल एप का नाम क्या है?
a) दृष्टि b) नजर c) आंख d) चक्षु
15. निम्न में से किस राजस्थानी विभूति पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है?
a) माघ b) मीराबाई
c) कन्हैयालाल सेठिया d) अल्लाह जिलाई बाई
16. राजस्थान में राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाओं की संख्या कितनी है?
a) 5 b) 6 c) 7 d) 8
17. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं किया जा सकता है?
a) गाय-भैंस (दुधारू) b) भेड़-बकरी (मादा)
c) ऊँट d) गधा - घोड़ा
18. अमृतादेवी इंडिजीनिस प्लांट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है?
a) मेनार उदयपुर b) देवमाली ब्यावर
c) खेजड़ली जोधपुर d) खीचन फलोदी
19. हाल ही में तंजानिया में स्थित माउंट किलीमंजारो चोटी फतह करने का कीर्तिमान किसने हासिल किया है?
a) राकेश विश्रोई b) दीपिका सिंह राठौड़
c) पूनम कंवर d) गीता सामोता
20. टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है?
a) डॉक्टर कैलाश सांखला b) मुकुल वासनिक
c) अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव d) विजय शर्मा
21. राजहंस किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है?
a) हनुमानगढ़ b) नागौर c) बारां d) भीलवाड़ा
22. राजस्थान वन विभाग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैन्यकर्मियों के सम्मान में नवजात गोडावण के चूजों का नाम क्या रखा गया?
a) सिंदूर व सोफिया b) व्योम व मिश्री
c) अभिनंदन व मोहना d) a और b दोनों
23. राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृतादेवी बिश्रोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
a) मुकुट मणिराज b) डॉ गौरीशंकर शर्मा
c) भोगीलाल पाटीदार d) पूनमचंद गोदार

प्रश्नोत्तरी नं. - 01 (उत्तर) 1.(i), 2. (ii), 3. (i), 4. (iii), 5. (iv), 6. (iii), 7. (i), 8. (iii), 9. (iii), 10. (ii), 11. (iii), 12. (i), 13. (i), 14. (i), 15. (i), 16. (iii), 17. (i), 18. (ii), 19. (iv), 20. (i), 21. (iv), 22. (iv), 23. (iv), 24. (ii)

प्रश्नोत्तरी नं. 1 के विजेता - गोलू कुमार गुर्जर (दौसा)



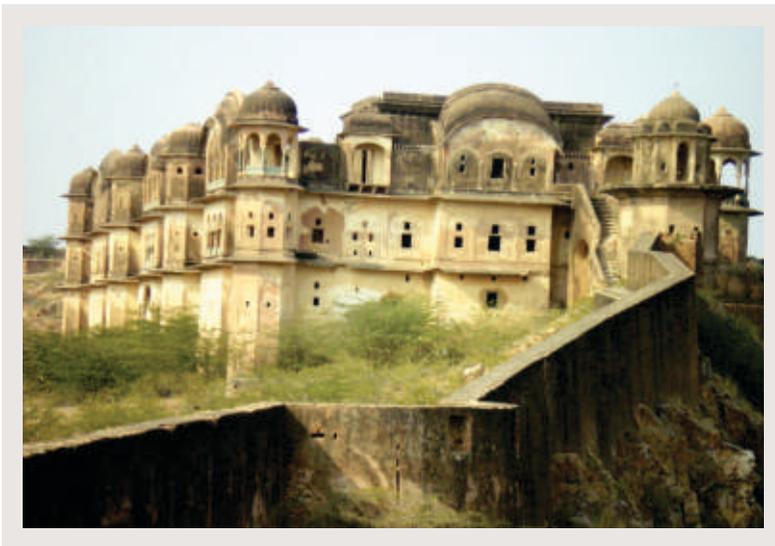
हवामहल का 'पुरखा'



खेतड़ी महल झुंझुनूं

राजस्थान के झुंझुनूं में स्थित खेतड़ी महल शेखावाटी की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसे 1770 में ठाकुर भोपाल सिंह ने बनवाया था। अपनी अनूठी संरचना और हवामहल के निर्माण की प्रेरणा होने के कारण यह 'खेतड़ी का हवामहल' और 'पवन पैलेस' भी कहलाता है।

हवामहल से अलग, महल में दरवाजे और खिड़कियां की कम संख्या के बावजूद हवा का प्रवाह हर हिस्से में बना रहता है। गर्मियों की तपिश से बचाने के लिए इसमें दीवारें कम और स्तंभ अधिक रखे गए हैं। महल की सबसे बड़ी विशेषता इसका रैंपनुमा ढांचा है, जिससे घोड़े पर सवार होकर भी छत तक पहुंचा जा सकता था। खेतड़ी महल से प्रभावित होकर ही महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में 1799 में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण कराया। ■



पीला पलाश

प्रदेश में दुर्लभतम वृक्ष – पीला पलाश

वानस्पतिक नाम – *Butea monosperma var. lutea*

सामान्य नाम – पलाश, किंशुक, ढाक, टेसू

स्थानीय नाम – पीला, खांखरा, ढोल, खाखरा



पीला पलाश (*Butea Monosperma Var. lutea*), पलाश की राजस्थान में अत्यंत दुर्लभ रूप से मिलने वाली एक प्रजाति है, जिसे लाल पलाश या 'फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट' का ही एक दुर्लभ प्रकार माना जाता है। सामान्य पलाश जहां लाल-नारंगी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पीला पलाश अपने सुनहरे पीले फूलों के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, अलवर और डूंगरपुर और कुछ अन्य जिलों में अत्यधिक सीमित रूप से पाया जाता है। बीजों का कमजोर अंकुरण, आनुवांशिक म्यूटेशन और आवास नष्ट होना इसके दुर्लभ होने के प्रमुख कारण हैं। पलाश के हजारों पौधों में कोई एक पेड़ पीले पलाश का होता है।

लुप्तप्रायः पौधों की श्रेणी में शामिल पीले पलाश के फूलों से भी लाल पलाश की तरह होली के लिए सुरक्षित प्राकृतिक रंग बनाया जा सकता है। स्थानीय लोग इसे शुभ मानते हैं और इसकी छाल का उपयोग पूजा-पाठ और पारंपरिक औषधियों के रूप में करते हैं। पलाश का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों, जैसे कृमिनाशक, मधुमेह और त्वचा रोगों में किया जाता है, पत्तों का उपयोग पतल-दोना बनाने में भी होता है।

वन कटाई, चराई और अंधाधुंध दोहन के कारण यह लुप्तप्रायः श्रेणी में है। इस दुर्लभ प्रजाति का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। ■



राजस्थान सुजस का यह अंक
<https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702>
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

